

The motion was adopted.

MR DEPUTY CHAIRMAN: Now, once the Statutory Resolution is voted, the Motion moved by Shri Shiva Chandra Jha is automatically barred.

SHORT DURATION DISCUSSION

Import of Animal Tallow

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we can start the discussion, on the other thing. Mr. Mathur, you can start now. Ten minutes' time is there. Please speak for ten minutes now.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, आज हम एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, परन्तु भावनाओं के भरे हुए विषय पर विचार करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब गाय के मांस की या सुअर की चर्बी का जिक्र आता है तो स्वभावतः रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को वह दिन याद है जब आज से एक सदी पहले इस सवाल को मुख्य बनाकर हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की थी। मेरे साथी जो इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, वे कहेंगे कि एक सदी बीत गई, लेकिन हिन्दुस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। हम प्रोग्रेसिव या प्रगतिवादी नहीं हुए। आज भी मुसलमान सुअर के मांस को हाथ लगाने से डरता है और गऊ के मांस का नाम लेने में हिन्दु भी नाराज हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि तथाकथित प्रोग्रेसिव कहलाने वाले लोग इस संबंध में ठीक या गलत विचार रखते हैं मगर यह सत्य है कि गाय और सुअर का मांस छूने से हिन्दु मुसलमान नाराज होता है। इस वक्त यह बहस का विषय नहीं है। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि लोगों को भावनाओं का निरादर नहीं किया जाना चाहिए। यह कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं है। प्रत्येक धर्म की कुछ न कुछ

मान्यताएँ होती हैं। इस देश के हिन्दू यह मानते हैं कि गाय उनके लिए माता के समान है। मुसलमानों के लिए सुअर का मांस हराम है। इसमें कोई पिछड़ेपन की बात नहीं है। इससे भावनाओं का संबंध है, मजहबी अकीदा है। इससे कहीं पर पिछड़ापन प्रलक्षित नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि जब गाय और सुअर की चर्बी का सवाल उठा तो सरकार ने इसको राजनीति का सवाल बना दिया। सवाल इस बात का नहीं है कि चर्बी बाहर से आती है। देश में भी चर्बी पैदा की जा सकती है। सवाल यह है कि हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? हमारे विद्वान मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं। पहले पहल जब यह सवाल खड़ा हुआ तो मंत्री महोदय ने लोक सभा में 25 जुलाई को कहा कि चर्बी का कुछ आयात होता है, लेकिन इसमें मिलावट की कोई गुंजायश नहीं है। चार दिन के बाद कहा कि हाँ, मिलावट हो सकती है और हम इसको पकड़ेंगे। फिर कहा कि मिलावट पे मिलावट नहीं हो सकती है। आज कहते हैं कि हमने कुछ मामले पकड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब यह सवाल खड़ा हुआ था, तो उस वक्त खुले आम यह क्यों नहीं कहा गया कि हाँ, मिलावट हो सकती है, हम मामले पकड़ रहे हैं। इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती। लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले को एक राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि 25 जुलाई से अगस्त और सितम्बर तक आपने अलग अलग ध्यान क्यों दिये? इसका स्पष्ट कारण यह था कि आप मामले को दबाना चाहते थे। जब मिलावट हो सकती थी तो आपने पहले ही मामले की छानबीन क्यों नहीं की? श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आप जैसे

विद्वान और मजबूत मंत्री के होते हुए आपने इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों की ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) :
वे तो बहुत कमजोर व्यक्ति हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपके मुकाबले में कमजोर व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन मेरे मुकाबले में तो तगड़े हैं। जब सर्वप्रथम यह सवाल खड़ा हुआ तभी सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह कहती कि गाय की और मुअर की चर्बी देश में आती है और उसकी मिलावट भी हो सकती है। लेकिन इस मामले की जांच करेंगे और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको सजा देंगे। अगर आप ऐसा करते तो विरोधी दल और सरकार, सभी मिलकर उसका मुकाबला करते। लेकिन श्रीमन्, इन्होंने एक नया चैप्टर खोल दिया। कह दिया कि जनता सरकार के दौरान आयात खोला गया था। यह कहने की आवश्यकता क्या थी? सीधा सवाल था। इनको लगा कि अगर मान लिया गया कि चर्बी या मुअर की चर्बी देश में आ रही है तो सरकार की छवि को नुकसान होगा। हमने राजनीतिक सवाल नहीं बनाया था। इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि जनता सरकार के दौरान यह किया गया था जो कि असत्य है, गलत है। स्थिति यह है कि... (व्यवधान)...

आप अभी मंत्री नहीं बने हैं। मंत्री बनकर पहले आगे बैठ जाइये फिर जवाब दीजियेगा... (व्यवधान) ... वही बताता हूँ... (व्यवधान) ...

श्रीमन्, मुझे बहन उषा मल्होत्रा जी को इस प्रकार लड़ता देखकर बड़ा दुःख होता है। मुझे उस शरीफ आदमी के ऊपर बड़ा भरोसा पैदा होता है। वह

कितना बड़ा और सहनशील आदमी होगा, कितना शानदार होगा। अर्थात् मुझे भी श्री मल्होत्रा जी के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह कितना शरीफ आदमी है जो कि हमारी इस बहन को बर्दाश्त किए हुए हैं... (व्यवधान)...

श्रीमन्, यह कहना कि जनता सरकार के दौरान यह किया गया, यह भी सरासर गलत है। तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं। हां ऐसी कुछ आइटम थे, जो बैं नहीं थे, न चैनालाइज थे और न रस्ट्रिक्टेड थे। ऐसी कुछ चीजों को छोड़ कर कहा गया था कि जो आइटम इस लिस्ट में नहीं हैं, वे ओ० जो० एल० आ सकते हैं। मान लिया यह नजरान्दाजी हो गई लेकिन श्रीमन्, गाय की चर्बी लाई कब गई? यह कांग्रेस (आई) सरकार के दौरान लाई गई। जैन शुद्ध वनस्पति जिस संरक्षण के लिये आप खड़े होंगे, जा साहब खड़े हो चुके हैं... (व्यवधान) आज प्रश्नोत्तर काल के अन्दर खड़े हो चुके हैं, वे खड़े होंगे और हो सकता है कि इन्होंने आफिसरों और मंत्रियों के साथ मिलकर... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह सवाल खड़ा किया गया क्योंकि गाय की चर्बी का नाम यहां सूची में अलग से नहीं लिखा गया है इसलिये हम इसका आयात कर सकते हैं। यह नया कानून या तरीका किसने निकाला और कहां से निकला? आपकी सरकार के आफिसरों ने शुद्ध जैन वनस्पति के लोगों से मिलकर निकाला, दूसरे लोगों से मिलकर निकाला और मुझे संदेह है कि शायद इसमें हाथ खाली आफिसरों का ही नहीं है, ऊपर तक का भी है : ऊपर तक का भी है... (व्यवधान) ... मैं साबित करूंगा यादव जो अभी साबित करूंगा।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : मैं साबित करूंगा कि आपने पलड़ गेट खोलकर, एक्सपोर्ट पालिसी को चँज करके यह किया।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यादव जी बीच में खड़े हो गये। आदत है, उससे मजबूर हैं, क्या करें : लेकिन जब इन्होंने कहा है... (व्यवधान)...

श्री रामानन्द यादव : आपको आदत ऐसे ही बकवास करने की है, अनर्गल बातें करने की है, अन-पार्लियामेंटरी बातें करने की है.. (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आंकड़े इस बात के सबूत हैं। जनता सरकार के दौरान कहीं मिलावट नहीं हुई। यद्यपि चर्बी उस समय इम्पोर्ट होती थी। उस समय तेल के दाम कम थे और चर्बी महंगी थी, इसलिये चर्बी की मिलावट का सवाल ही खड़ा नहीं होता था और मिलावट को नहीं जाता था। लेकिन कांग्रेस (आई) की सरकार आने के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई और चर्बी सस्ती हो गई, इसलिये मिलावट आई। हाँ, जनता सरकार के वक्त चर्बी आती थी लेकिन उस समय मिलावट नहीं होती थी। इसलिये सवाल उसके इम्पोर्ट का नहीं है, उसके कानून का नहीं है। लेकिन आप इसे इम्पोर्ट का सवाल बना रहे हैं। सवाल चर्बी के दुरुपयोग करने का है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर उनके पास कोई केस है कि जनता सरकार के दौरान चर्बी की मिलावट हुई थी तो उसको सामने रख दें। अगर होता तो पहले दिन ही रख देते। लेकिन कोई मामला है ही नहीं। क्योंकि चर्बी महंगी और तेल सस्ता था। लेकिन जब तेल महंगा हो गया और चर्बी सस्ती हो गई तो तब-कथित ईमानदार लोगों ने सरकार के आफिसरों और मंत्रियों से मिलकर पैसा कमाना शुरू किया। जिसमें से एक करोड़

से अधिक रुपया पिछले चुनाव में कांग्रेस (आई) पार्टी को शुद्ध जैन धन्यमति ने दिया... (व्यवधान)...

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : एकदम गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है... (व्यवधान)...

श्री जगदीश प्रसाद यादव : आपको कैसे पता लगा कि गलत है... (व्यवधान)...

1.00 p.m.

श्री रामानन्द यादव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं साबित कर दूंगा (व्यवधान)।

श्रीमती उषा मल्होत्रा (हिमाचल प्रदेश) : जैन द्यूब वाले (व्यवधान) इनको सिस्टर कनसर्न हैं उन्होंने किया है आप जानते हैं इस बात को (व्यवधान) आपको पार्टी के है (व्यवधान)।

श्री उपसभापति : यादव जी, आपका क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री रामानन्द यादव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि हम लोग इस सदन में जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारों के साथ कोई एलोगेशन लगाते हैं और उन एलोगेशंस के बारे में हमारे क्लेज एंड रेगुलेशंस हैं उसमें दिया हुआ है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जैसी आप कर रहे हैं।

श्री रामानन्द यादव : जो डाकुमेंटरी नहीं, हैं सुनी सुनाई हैं, हीयर से हों उनके आधार पर एलोगेशन नहीं लगाने चाहिये। वह डाकुमेंटरी होंनी चाहिये। किसी कोर्ट में एवीडेंस होना चाहिये, किसी के

पास कोई कागजात हो तो हम एलोगेन्स लगा सकते हैं। यह किताब है आप देख लीजिये। जहाँ हमने कोई स्टेटमेंट देना है कोई स्पीच देनी है, उसमें बिलकुल लिखा हुआ है (व्यवधान) बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कोई एलोगेशन हम को लगाना है। क्योंकि माथुर साहब की हेबिट है कि वे गैर जिम्मेदाराना अन-नसेसरी एलोगेशन लगाते हैं और वह उसको केपचर कर लेते हैं क्या इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है या नहीं? क्या किसी भी सदस्य को कुछ भी कहने का अधिकार है? चाहे आपकी पार्टी हो या मेरी पार्टी हो बिना किसी डाकुमेंटरी एबोर्ड्स के या ओरल एबोर्ड्स कोर्ट में हुआ हो, क्या हम इस तरह से एलोगेशन लगा सकते हैं, इस पर मैं आपको क्लिग चाहता हूँ।

श्री उपसभापति : यह बात ठीक है जब कोई माननीय सदस्य इस तरह की बातें किसी के सम्बन्ध में किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध कहें तो जिम्मेदारी के साथ कहें और उनके पास कोई आधार भी कहने का होना चाहिये। केवल आरोप मात्र नहीं लगाना चाहिये। यह उचित नहीं है।

श्रीमती उषा मल्होत्रा : मेरे पास हंस राज गुप्ता का यह डाकुमेंटरी प्रूफ है (व्यवधान)।

श्री उपसभापति : जो विषय है उस पर कहें।
The discussion will continue after lunch.
सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at four minutes past one of the clock.

2 P.M.

The house reassembled after lunch at four minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.
MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन्, खाने के लिए छूटने से पहले मैं अपनी बात कह रहा था। श्रीमन्, मुख्य सवाल यह नहीं है कि गाय की या सुअर की चर्बी का कितना आयात हुआ है और किसने किया है, क्योंकि यह बहुत पहले से होता रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुख्य प्रश्न यह है कि उसका दुरुपयोग कहाँ, क्यों और किसने किया है?

सरकार की जो एक प्रिय कम्पनी है, मैं उसका उल्लेख कर रहा था— जैन शुद्ध वनस्पति। जब मैंने यहाँ एक सच्ची बात कही कि उसने एक करोड़ रुपया कांग्रेस के फण्ड में दिया मेरे कुछ साथी बहुत नाराज हो गये थे।

श्रीमन् मैं अपनी बात को सुधारना चाहता हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि एक करोड़ रुपया चुनाव के समय दिया गया था और पांच करोड़ अब दिया जा रहा है शुद्ध वनस्पति के इस मामले को दबाने के लिए। तो मैं अपनी बात का संशोधन कर रहा हूँ।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : झूठ बात है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : झूठ नहीं है, आप मूढ़ मत खलवाओ।

श्री कल्पनाथ राय : इन का आरोप निराधार है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप यह कहेंगे ही। (व्यवधान) मैं साबित करने को तैयार हूँ। कांग्रेस (आई) के एकाउन्ट्स और शुद्ध वनस्पति के एकाउन्ट्स आडिट करने का अधिकार दे दें तो हम साबित कर देंगे।

श्री रामानन्द यादव : यही जिम्मेवार ढंग से बात करने का तरीका है?

[श्री रामानन्द यादव]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप की प्रधान मंत्री इस सदन में कह कर जाती हैं कि बी० जे० पी० वाले राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हैं इस से बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आज से दो साल पहले इसी सदन में उन्होंने कहा था। उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करते बी० जे० पी० वाले। वह आरोप इस से बड़ा है। आप लोग तो इतनी बड़ी और गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। (व्यवधान) मैं सच कह रहा हूँ कि कांग्रेस को पैसा दिया गया।

श्री उपसभापति : जरा रुकिये।

श्री संयद रहमत अली (आन्ध्र प्रदेश) : जब मोहतरिम माथुर साहब ने लंच से पहले इस मसले को उठाया था तो यादव जी की तरफ से रूलिंग चाही गयी थी और आप ने रूलिंग दी है। अगर उस के बाद भी माथुर साहब दोबारा जिक्र करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह कायदे और कानून के खिलाफ बात होगी। आप उन को यह दोहराने की मेहरबानी कर के इजाजत न दें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं दोहराऊंगा नहीं कि कांग्रेस को पैसा दिया गया।

श्री उपसभापति : जो विषय है उस पर आइये, आप सारा समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह सच्ची बात है जो जगह जगह कही जाती है और इस का सबूत है। मुबह मंत्री महोदय श्री आ साहब ने स्वीकार किया है और दूसरे मंत्री महोदय ने भी कहा कि शुद्ध वनस्पति वाला ने अनश्वर-राइज्ड रूप से चर्बी इम्पोर्ट की है और

उस के खिलाफ कस्टम्स की दृष्टि से कानूनी कार्यवाही की गयी है। यह इन्होंने माना है। मैं उस जजमेंट से कोट कर रहा हूँ जिस का हवाला प्रश्नोत्तर काल में श्री आडवाणी जी ने दिया था। कोर्ट कहता है :

"The material on the basis of which the above statement has been made has not been disclosed to the detinue. The documents placed on the record show that about 17,000 tonne* of beef tallow were imported against a licence. There were objections to the legality of the import. The Collector of Customs by an order dated 24th May, '83, (Ann. E) confiscated the goods but had given the importer the option to pay the fine mentioned therein in lieu of confiscation and clear the goods for home consumption."

यानी कोर्ट यह कहता है कि जो माल पकड़ा गया उस के पकड़े जाने पर उस को कहा गया कि तुम फाइन दे कर माल छुड़ा सकते हो। आगे कोर्ट कहता है :

"About 7,000 tonnes of beef tallow was cleared on payment of fine and part of it was sold by the petitioner to Manoj Containers."

फाइन देकर बीफ टेलो छुड़ा लिया गया और कोर्ट के अनुसार इस में से कुछ हिस्सा पंजाब के मनोज कन्टेनर्स को दिया गया। यह रिकार्ड में है। मवाल यह है कि शुद्ध वनस्पति स्वयं कन्ज्यूमर नहीं रहा, उसने चर्बी बेची है, कोर्ट के सामने भी यह विषय आया है मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि फिर आप ने उन के खिलाफ इस बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की। आप ने माल पकड़ा। माल पकड़ने के बाद फाइन दे कर छुड़ा दिया, माल छूट कर आ गया तो वह आदमी उसे आगे बेचता है और आप कहते हैं कि उस का लाइसेंस कैसे कैमिल कर दें। क्यों नहीं कर सकते।

एक जुर्म नहीं है, दसियों जुर्म इस कम्पनी के खिलाफ हैं। आप का स्टेटमेंट है मेरे सामने :

"According to the record of facts placed before the Singapore court, the conspiracy was allegedly hatched by Shri R. K. Jain, Shri B. K. Jain, who own large groups of companies in India, namely Jain Shudh Vanaspati Ltd. and Jain Exports Pvt. Ltd."

यह सिमापुर के कोर्ट में साबित हुआ है कि इन लोगों ने जालसाजी द्वारा जाली माल भेज कर जहाज को डुबो दिया।
It is a fact.

सरकार ने खुद कहा है कि सी बी आई इस को जांच करेगी। इस कम्पनी पर और भी चार्ज हैं। पंजाब सिंध बैंक के बारे में लोक सभा में सवाल किया गया और वित्त मंत्री जी ने जवाब में कहा कि पूरी बता नहीं सकते।

वाणिज्य और पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं हर एक बात का जवाब दूंगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : पंजाब सिंध बैंक के साथ क्या किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है उन्होंने कहा कि वे उस बात को खोल नहीं सकते। पंजाब सिंध बैंक का मामला यह है कि शुद्ध बनस्पति वालों का लेटर आफ क्रेडिट था 588.83 लाख का और प्रूजेन्स बिल्स ड्रान था 1361.62 लाख का और उन की कुल संपत्ति कितनी है? कुछ लाख की लेकिन उन को पैसा कितना मिला है? 25 करोड़ सारे कायदे कानून तोड़ने के बाद पंजाब सिंध बैंक जो कि गवर्नमेंट का बैंक है उस ने 25 करोड़ रुपया इन की दो कंपनियों को दिया जितनी उन की कुल लागत है उस से चौगुना उन को दिया है। यह केवल इन दो कंपनियों को पैसा देने मात्र का ही सवाल नहीं है। यह बैंक के साथ फ्राड है,

सारे देश के साथ फ्राड है। उस के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम इसी शुद्ध बनस्पति कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। सवाल सीधा है कि कहीं न कहीं इस दलाली में सरकारी दल के हाथ काले हैं। इसलिये श्रीमन, मेरा कहना है कि सवाल इतना छोटा नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप अपने दल के स्वार्थ के लिये, केवल सरकार के बचाव के लिये या कुछ अफसरों के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये हिन्दुस्तान के हिन्दु मुसलमानों की भावनाओं से खेलना चाहते हैं? अगर खेलना चाहते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। हरगिज अच्छा नहीं होगा। आप को इस सवाल पर ईमानदारी से राजनीति में ऊपर उठ कर सदन को आश्वासन देना चाहिए कि जो चाहे कंपनी हो, गड़बड़ी करने वाले को हम सजा देगे और कड़ाई के साथ सजा देगे। बजाय अपने या अपने दल के स्वार्थ और हित को देखने के। अगर आप ईमानदारी से काम ऐसा करेंगे तो इस मामले में हम आप के साथ होंगे।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) :
उपसभापति महोदय...

श्री उपसभापति : आप का नाम है। इस में सब बोलेंगे।

श्रीमती उषा मल्होत्रा : जिन समय माथुर साहब अपनी बात कह रहे थे तो मैंने डाक्यूमेंट पेश करने की बात कही थी कि क्या कोई ऐसे कागज है कि जिन के आधार पर वे साबित कर सकें कि यह गलत काम हुआ है। मेरे पास एच डक्यूमेंट है जो मैं आप के साम-

[श्रीमती ऊषा मल्होत्रा]

पेश करना चाहती हूँ। इस में हंसराज गुप्त जो हैं...

श्री रामेश्वर सिंह : जब आप बोलियेगा तो उस को रखियेगा।

श्रीमती ऊषा मल्होत्रा : आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते। वे इस के संचालक हैं और इन का यह सिस्टर कंसर्न है जिन्होंने यह इपोर्ट किया है बोफ टैलो और एनीमल टैलो और उन्होंने किसी अनलाइसेस्ड मैन्युफैक्चरर को दिया है। अब वह बतलाये कि यह कौन है? एक बात और सुनिये। यह किस पार्टी को बिलॉग करते हैं? जनता सरकार को। क्या यह उस वक्त कायम नहीं हुई? क्या उन को इजाजत नहीं दी गयी कि इस को वे बाहर से मंगायें? हंसराज गुप्त और दूसरे जो हैं क्या उन्होंने अपने ओहदे को मिसपूज नहीं किया है और उस के बाद इसको अनलाइसेस्ड मैन्युफैक्चरर को नहीं दे दिया? क्या उन्होंने ऐसा कर के धोखा नहीं दिया है...

(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं (व्यवधान) आप जिस चीज को इतना लम्बा खींचने जा रहे हैं और जिस की वजह से वनस्पति का उत्पादन बंद कराने जा रहे हैं तो ऐसा होने पर गरीब आदमी खायेगा क्या? हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह ऐसा कदम उठाये कि जिस के कारण शुद्ध वनस्पति तो बनता रहे और ऐसे स्ट्रिजेट मेसजर्स लिये जायें जिस से मिलावट बंद हो। (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उन्होंने हंसराज गुप्त का नाम लिया है (व्यवधान)

श्रीमती ऊषा मल्होत्रा : विदेश में जायेंगे तो क्या साबुन और तौलिया

साथ ले कर जायेंगे? तौलिया भी तो इसी से धुलता है। किसका क्या करोगे आप? वह आज इसी साबुन से धुले हुए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती मौनिका दास (कर्नाटक) :

500 करोड़ रुपया किसने खाया? आप ने उसका हिसाब दिया? कोई हिसाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप लोग बैठिये, बस हो गया।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उषा वहन ने लाला हंसराज का नाम लिया है। लेकिन इन्होंने उस कंपनी का नाम नहीं लिया जिनके वह हैं। वह कंपनी जैन शुद्ध वनस्पति कंपनी है। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : अब हो गया। श्री रामानन्द यादव जी को बोलने की-जिए। आप बहुत कह चुके हैं। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्रीमती मौनिका दास : गवर्नमेंट को फेल करने के लिए ये ऐसा कह रहे हैं।

श्री उपसभापति : आपका जब टर्न आयेगा तब आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : लाला हंसराज जी का नाम लिया है और इन्होंने यह दिखाया है जैसे लाला हंसराज जी कोई अलग कम्पनी हैं। लाला हंसराज जी 1975 तक जैन शुद्ध वनस्पति से संबंधित थे। 1975 में वह अलग हो गये थे उन्होंने कंपनी से अपना सम्बन्ध छोड़ दिया है। इसलिए लाला जी के प्रति यह कहना बिलकुल गलत है और जैन शुद्ध वनस्पति उद्योग के लिए मैंने जो चार्ज लगाया है वही सच है। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : बस हो गया, श्री रामानन्द यादव ।

श्री रामानन्द यादव : मान्यवर, मुझे हिन्दी की एक कहावत याद आ रही है । एक मुहावरा है—उल्टा चौर कोत-वाल को डंटे । यह मुहावरा बड़ा मशहूर है । ये क्लप्रिट्स, गुनहगार लोग जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा कह रहे हैं । इन लोगों ने सब से पहले इस प्रश्न को उठाया और उल्टे यह कह रहे हैं कि हमारे कामर्स मंत्री ने इसे उठाया ।

[उपसभापति (श्री संजय रहमत अली) पोटासीन हुए]

श्रीमन् इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी और श्री चरण सिंह जिन लोगों का आजकल एक अनहोली अलायंस हो गया है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, यह अलायंस करके दोनों एक मुंह लगाकर एक शब्द यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गाय को चर्बी का आयात शुरू किया ।

मान्यवर, यह बात सही है कि हर तरह की एनीमल चर्बी का आयात देश में होता था लेकिन यह कैनालाइज था । अपने देश में यूजर्स के लिए और स्ट्रिक्टली फोलो होता था और लाइसेंस को एक्जोक्लूट करने में और साथ ही उसके यूज में कुछ नियम थे । लेकिन जैसे ही जनता पार्टी आई, जनता पार्टी के वरिष्ठ हकदार, जनसंघ के बैठे हुए हमारे साथी माथुर साहब जो भी अनगल बातें कर गये और उनके दूसरे पार्टनर-रामेश्वर सिंह जी, जो यहां बैठे हुए हैं, लगातार लोक दल के, आजकल इनके

साथ हनीमून कर लिये हैं, गठबंधन कर लिए हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : आपको क्या परेशानी है ? (व्यवधान)

श्री रामानन्द यादव : हमको परेशानी कुछ नहीं है । हम कहते हैं कि यह अनहोली मैरिज नहीं चलेगी, तलाक जल्दी होने वाला है ।

मान्यवर, इन लोगों ने पी० सी० अलेक्जेंडर कमेटी बनाई । पी० सी० अलेक्जेंडर कमेटी जनता पार्टी रिजिम में उनके कैबिनेट डिसिजन से बनी । यह 1977 में बनी । किस लिये बनी ? यह इसलिए बनी कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की जो पालिसी है इसका स्ट्रक्चर रिवाइज किया जाए । इसकी फंक्शनिंग ठीक की जाए, इम्पोर्ट के ऊपर विचार किया जाए कि कहीं गड़बड़ है या नहीं । पी० सी० अलेक्जेंडर ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में इम्पोर्ट की जो आइटम्स हैं उनको विभाजित किया । एक परमिसिबल किया, एक बैन किया है और एक केनालाइज किया । हर तरह के टैलो का आयात इस देश में कैनालाइज तरीके से होता था । वह एक्चुअल यूजर्स को दिया जाता था । जो आइटम्स परमिसिबल में, बैन में या केनालाइज में नहीं थी वे ओपन जनरल लाइसेंस में हो गई । इनके भूतपूर्व कामर्स मिनिस्टर धारिया साहब ने खुद स्वीकार किया है कि ये आइटम्स ओपन जनरल लाइसेंस में आ गई । अब फ्री हो गई । ये आइटम न तो परमिसिबल में रहें, न बैन रही और न केनालाइज में रही । उसको अगर माथुर साहब चाहते तो वह भी इम्पोर्ट कर सकते थे । इस चर्बी की आइटम को निकाल कर एनीमल टैलो को निकाल कर, नाइस परमिसिबल, नार बैन, नार कैनालाइज

[श्री रामानन्द यादव]

इन तीनों के अंदर न रख कर इन गुनाहगार लोगों ने फ्लड गेट खोल दिया। कोई भी आदमी उस चर्बी को आयात कर सकता था।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Yadavji, I don't want to take part but I only want to inform you that Open General Licence is also for actual users. Actual users require licence but not Open General Licence. That was a liberalised procedure which your Government also is following. Don't talk something which is wrong. You do not know what you are talking.

SHRI SAT PAUL MITTAL (Punjab): He does not require a certificate from you.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: Mr. Kulkarni... (Interruptions) ...

SHRI A. G. KULKARNI: Madam, I am not a bachelor like Mr. Mathur to report. Otherwise I would.... (Interruptions) ...

SHRI RAMANAND YADAV: You are a super democrat. You hear me. I know your weakness. You are partners of the Janata group. (Interruptions)

श्री रामानन्द यादव : उसी के मातहत फरदर धारिया साहब कहते हैं...

श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी : आप किसान हैं। आप अलग सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। आप किसानों की बात करिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : कुलकर्णी साहब आपका नाम भी है।

श्री रामानन्द यादव : यह मेरा समय ले रहे हैं। यह मेरे समय में शामिल नहीं होना चाहिये। धारिया जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है....

श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी :

धारिया साहब की स्टेटमेंट मेरे पास है। उसमें लिखा है इट इज फार एक्चुअल यूजर्स. If you don't know, you please read it.

SHRI RAMANAND YADAV: I have got the statement. If you like, I will show you what he has said. उन्होंने कहा है कि किसी वनस्पति कम्पनी ने चर्बी का आयात नहीं किया। लेकिन धारिया साहब के रिजिम में जितने गुनाहगार लोग जनता पार्टी के ओल्ड डिफेक्टर्स, हू वेट देयर, गवर्नमेंट बनाई, उस गवर्नमेंट के लोगों ने 25 हजार टन बीफ टैलो इम्पोर्ट किया इस देश में। यह रिकार्ड में है। जनता पार्टी के रिजिम में जब धारिया साहब कामर्स मिनिस्टर थे तो 25 हजार टन बीफ टैला इस देश में इम्पोर्ट हुआ। अगर धारिया साहब के कथनानुसार यह चर्बी वनस्पति कम्पनियों ने यूज नहीं की तो दूसरे लोगों ने तो की होगी। इसलिये जब आप लोग गवर्नमेंट में थे तो क्या आप सोचे हुये थे? आज आप गो-भक्त बनते हो क्योंकि आपको मालूम है कि चुनाव आ रहा है, पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक है, इसलिये आपने समझा कि यह गोला भी मिल गया। इस इशू को आपने उठा दिया। धारिया बेचारे आनेस्ट आदमी हैं। वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि चर्बी मंगाना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मैं आप गुनाहगारों से पूछना चाहता हूँ कि आप उस वक्त गवर्नमेंट के पार्ट एण्ड पार्सल थे, आपने इसको क्यों बैन क्यों नहीं किया? हमारी सरकार को जब मालूम हुआ कि इसकी मिलावट होती है तो श्री विश्वनाथ

प्रधान सिंह जी ने सब प्रकार की एनीमल चर्बी को बैन कर दिया। आपको उनका धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन आप में कोई लाज-शर्म नहीं है। अरे नि-लैज लोगो! तुमने अपनी सरकार बनाई, तीन वर्ष तक आप शासन में रहे, आपने, जनता सरकार ने, 25 हजार टन गाय का चर्बी इस देश में मंगाई। आपने इसको बैन नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इसको बैन क्यों नहीं किया? क्या आप में कोई लाज-शर्म या इज्जत है? लोक सभा में जब यह प्रश्न उठा तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री चरण सिंह ने सोचा कि अब क्या करना चाहिये दोनों ने मन्त्रणा की और सोचा कि अडलट्रेशन का इशू उठाया जाये। इम्पोर्ट का इशू छोड़ दिया जाये। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप शासन में थे तो आपने यह अडलट्रेशन का इशू क्यों नहीं उठाया? अगर आप कहते हैं कि आपके टाइम में अडलट्रेशन नहीं होता था तो इसका मतलब यह है कि आप इस देश के पूँजीपतियों से मिले हुये थे। जो लोग टैलो मंगाते थे, आपने उनका रेड नहीं किया, उनको छानबीन नहीं की। चर्बी मंगाने वाले आपसे मिले हुये थे। इसलिये आपके सामने इस तरह के केसेज नहीं आए। लेकिन हमारी सरकार ने 90 फैक्ट्रियों के चार हजार के करीब सैम्पल लेकर उनकी जांच करवाई। उनका रिजल्ट आपके सामने माननीय मन्त्री जो रख चुके हैं। लेकिन आपमें कोई लाज-शर्म हो नहीं है। कांग्रेस सरकार ने फैक्ट्रियों में रेड किया है और प्रोसियेशन भी शुरू कर दिया है। आपने 25 हजार टन गाय की चर्बी मंगाई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि आप पूँजीपतियों से मिले हुये थे। वनस्पति कम्पनियों के अलावा भी दूसरी कम्पनियां हैं जो इसका दुरुपयोग कर सकती थी। कुछ कम्पनियां

साबुन आदि के लिये इसको मंगती है। लेकिन आपने इस सम्बन्ध में कोई कार्य-वाही नहीं की। आपने गाय की चर्बी को देश में आने से रोका नहीं, क्योंकि आपमें मिली-भगत थी। मैं जनता पार्टी की सरकार को वनियों की सरकार कहता हूँ। व्यापारियों की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने इसको बैन नहीं किया। लेकिन आज आप वोट क्लब में चले जाते हैं और इस तरह का स्वांग करते हैं। वोट क्लब में गये, दोनों एक साथ मिलकर स्वांग रचने लगे। लेकिन इस देश की जनता प्रबुद्ध हो गई है, समझदार हो गयी है। वह जानती है कि असल गुनाहगार आप हैं। आप ने अगर 1978 में अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पालिसी रिव्यू नहीं की होती और यह फ्लड गेट न खोला होता और ऐसे आइटमों को उसमें से निकाल कर ओपन आइटम के अन्दर नहीं रखते तो शायद ये चीजें नहीं होती। हमारे समय में भी आता था लेकिन वह एक्चुअल यूजर्स जो थे वही लेते थे, पूरी निगरानी रखी जाती थी कि कौन लेता है और उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसकी पूरी देखभाल होती थी, उस पर कंट्रोल था। आपने फ्री कर दिया और इस देश के पूँजीपतियों के करोड़ों रुपये आपने वनवाये। जो यह रुपया बना है इसकी जिम्मेदारी आप की है, जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह शुद्ध जो वनस्पति कम्पनी है क्या इसकी सप्लायरि जनता सरकार नहीं थी, क्या श्री हंसराज गुप्ता इसके डाइरेक्टर नहीं थे? अभी-अभी जो एक बड़ी विल्डिंग में आग लगी क्या आपके लोग उसके डाइरेक्टर नहीं थे? जहाँ कि गुनाह करने वाले लोग हैं, आपकी इस तरह की जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, उनमें सब आपके लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उससे श्री

[श्री रामानन्द यादव]

हंसराज गुप्ता का सम्बन्ध नहीं था ? उन्होंने अभी कहा कि रिजायन कर दिया। रिजाइन कर दिया तो यह तथाकथित किया गया होगा, बेटा हो गया होगा, जिसका पता नहीं है, उनके बदले उनका बेटा बैठ गया होगा, उनकी स्त्री हो गई होगी उनके दूसरे लोग हो गये होंगे...

(व्यवधान)... मान्यवर, ... (व्यवधान)

... आप देखिये पंजाब गवर्नमेंट, जो कि हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है उसने यह कार्य किया। इन लोगों ने हमारी नी स्टेट गवर्नमेंट्स को खत्म किया और जब ये इन राज्यों में सत्ता में आये तो इन सब स्टेटों में जनसंघ के आदमी जो कि गौ-भक्त हैं वह भी इनके साथ थे। लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जायेगी तो ये सबसे पहले उसको खोल देंगे, उस को फ्री छोड़ देंगे, फेंक देंगे, घर से निकाल देंगे। जब वह बूढ़ी हो जायेगी, दूध नहीं देगी तो ये बेईमान लोग उसको कहां भिजवा देंगे, कसाई खाने में। इसके बावजूद भी ये लोग आज गाय की चर्बी का हल्ला चुनाव को मददेनजर रखते हुये कर रहे हैं। वह आज यह भी चर्चा करते हैं इस पर ही 1957 का विद्रोह हुआ था। लेकिन आज हिन्दू और मुसलमान, दोनों इतने समझदार हो गये हैं कि इसका उन पर कोई असर नहीं है। ये समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यह 1957 वाला बात नहीं है। आज 1983 है, गांव गांव के लोग समझ गये हैं कि असल बात क्या है। आपने इस पर वैन नहीं लगाया। हमारी पंजाब सरकार ने, दरबारा सिंह की सरकार ने रेंड किया और कंपनियों को पकड़ा और उनके ऊपर हर तरीके से प्रोसीक्यूशन को तैयार कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन आप तीन वर्षों तक बैठे रहे। इतनी चर्ची यहां आई और एक बार भी आपने ऐक्शन

नहीं लिया। क्या आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी ? मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप पैसा लेकर चुपचाप बैठे रहे। मैं यही कहूंगा कि आप उनके दलाल हैं। आप इस देश के पूँजीपतियों के दलाल हैं और उन्हीं की वजह से यह सब आप कार्यवाही कर रहे हैं। यह भी सम्भव है कि आप चाहते हों कि हमारा व्यापार ठप्प पड़े और तेल का प्राइसेस इस देश में पैदा हो और वनस्पति का उत्पादन न हो। आप यह भी चाहते हैं, किसी खास कम्पन से, हो सकता है कि आप इन्टरस्टेड हों कि अमेरिका से रेपसीड मंगाया जाये। अमेरिका से इन्टरस्टेड होकर हो सकता है कि आप यह बात कर रहे हों ताकि वहां से रेपसीड आयात मंगाया जाय। यह भी बात है कि बड़ी जो फारेन पावर हैं...

(व्यवधान)...

SHRI HAREKRUSHNA MALICK (Orissa): When is the hon. Member addressing? (Interruptions)

On a point of order. He should address the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Please resume your seat. Don't interrupt.

श्री रामानन्द यादव : मान्यवर, अमेरिका इकोनोमिक लड़ाई लड़ने में बड़ा सक्षम है। यह अमेरिका के आजकल पिटठू बने हुये हैं। जो अमेरिका कहेगा यह वही कहेंगे। अमेरिका कहेगा हुआ तो यह कहेंगे हुआ और अमेरिका कहेगा धुआं तो यह कहेंगे धुआं। मान्यवर, सम्भव है कि हमारी जो वनस्पति की इंडस्ट्री है उसको नेस्तोनाबद्ध करने का गेम अमेरिका खेल रहा है ताकि यहां लोग वनस्पति न खरीदें और फैंक्रीज बन्द हो जायें जिससे इनका बाहर से रेपसीड आयात मंगाना पड़े और अमेरिका से मंगवायें और उसमें हमारा फारेन एक्सचेंज भी खर्च हो। यह तो अमेरिका के दलाल का काम कर भी

सकते हैं। मन्त्री जी ने तो अपनी बातें सभी कह दी हैं मान्यवर, मैं अब कुछ क्लेरोफिकेशन उनसे पूछना चाहता हूँ।

श्री रामेश्वर सिंह : अब आपके पास बोलने के लिये कुछ नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री रामानन्द यादव : मेरे 10 प्रश्न हैं। मैं इन पर मन्त्री जी से क्लेरोफिकेशन पूछना चाहता हूँ। मन्त्री जी इनको स्पष्ट करें। मेरा पहला क्लेरोफिकेशन यह है—

(1) Whether it is a fact that thousands of tonnes of beef tallow were imported under Open General Licence, not necessarily by actual users?

श्री आर० आर० मोरारका (राजस्थान): हिन्दी में बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : आप उनकी बात को सुनिये। अगर समझ में नहीं आ रही तो ट्रांसलेशन सुन लीजिये।

SHRI RAMANAND YADAV:

(2) Whether it is a fact that the Janata Government appointed the P. C. Alexander Committee in 1977 to review the structure and function of the import policy?

(3) Whether it is a fact that the Committee recommended the listing of import items under three major heads, "Permissible", "Banned", and "Canalised", and left beef tallow under Open General Licence?

(4) Whether the items not listed and classified under "Permissible", "Banned", and "Canalised" come under OGL?

(5) Whether the new Import Policy of 1978 and 1979 of the Janata Government

1132 RS—8.

removed all fetters on the import of beef tallow in the country?

(6) Whether it is a fact that all the Janata Government Ministers knew that beef tallow was imported during their time, nearly 25,000 tonnes, they did not ban it? Why did they not ban it? They did not ban it in spite of the fact that they knew fully well that 25,000 tonnes of beef tallow was imported during the Janata regime.

श्री रामेश्वर सिंह : कहिये तो मैं आपको किताब दे दूँ, रामानन्द जी।

SHRI RAMANAND YADAV: Next question.

(7) Whether it is a fact that beef and other animal tallow separate from vegetable oil and tallow gives out a strong odour and smell, ^rferrr fa^I^ «CT

(8) Whether it is a fact that the Opposition parties, the alliance of Lok Dal and BJP, are playing in the hands of Americans to propogate against vanaspati production in the country so that in large quantities the Government might be forced to import rapeseed from America, and create unrest and problems in this country?

(9) Whether it is a fact that one of the big leaders of the Jan Sangh, Shri Hans Raj Gupta, is a director of one of the subsidiaries of the Shudh Vanaspati Ghee and how he has ceased to be so and his benami, -his wife or daughter or son—anyone of these—is on the board of directors of the company?

(10) Whether it is a fact that all the adulterators of foodgrains are the friends and supporters of the Jan Sangh-Lok Dal alliance in the country?

श्री रामानन्द यादव : लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। जरा सुन लीजिए। आप तो इसे इमेन्शल कमाडिटी में रखा नहीं हैं।

[श्री रामानन्द यादव]

उपसमापक (श्री संयद रहमत अली):
आप उन्हें छोड़िये, अपना क्वेश्चन रखिये।

श्री रामानन्द यादव : जनता गवर्नमेंट ने तो वनस्पति को इसेन्शियल कमाडिटी में नहीं रखा है। इसलिए नहीं रखा कि वनस्पति को इसेन्शियल कमाडिटी में रख देते, तो इनके अपने लाग इक्वेट हो जाते, क्योंकि सब वनस्पति मैनुफैचरर्स जो थे इनके गाढ़े दोस्त थे। इनकी इलेक्शन में मदद करते थे और हर तरह से इनकी मदद करते थे। सम्भव है कि पैसे से मदद करते हों, वोट से करते हों, जैसे भी हो करते थे। क्या यह बात सही है?

(11) Whether the Government will place vansapati under the Essential Commodities Act?

इसलिए कि यह वनस्पति के पैदा करने वाले लोग अनफैटर्ब डंग से इसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं जिससे आम जनता उससे फायदा नहीं उठा पाती है और वनस्पति का भाव बढ़ता जा रहा है और गुनाह करने का रास्ता खुल जाता है।

इसलिए क्या सरकार वनस्पति को इसेन्शियल कमाडिटी के अन्दर ला कर के जो अनस्कूपलस एजेंट्स हैं, जो सम्भावना है कि वह मिला सकते हैं, इसको रोक सकें, क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

क्या सरकार यह महसूस करती है कि यह पोलिटिकल एल्गिन्स जो हैं, पोलिटिकल वैपेंस बना रहा है, जिसे सरकार को अपने प्रचार के यन्त्र के द्वारा इसका खण्डन करना चाहिए कि असली गुनाहगार ये लोग हैं, इनके समय में जितना बीफर्टेलो आया है, उस सब का काफी रूप से प्रचार किया जाए। क्या सरकार अपनी मजानरी द्वारा लोगों को अवगत कराने की कोशिश करेगी?

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) :
श्रीमन, एक ऐसी चीज पर बहस हो रही है जिस पर हिन्दुस्तान में करोड़-करोड़ आवाज के हर शरस को कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, वरना मूल जैसे लोग इस बहस में हिस्सा नहीं लेते।

मैं कुछ चीजें, मन्त्री महोदय से, सिर्फ अपनी जानकारी ही नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए भी चाहूंगा। एक बात तो मैं कहने में कुछ गुरेज नहीं है कि यह चर्ची का आयात तो पता नहीं कब से हो रहा है, शायद मन्त्री जी को भी मालूम हो कि यह आयात-निर्गत का व्यापार ही दामों की उथल कूद जैसे हिन्दुस्तान में होता है, उसके ऊपर आधारित रहता है। आन्तरिक चीजों के दाम जब बेतहाशा बढ़ने लगते हैं, बाहर की चीजों का, जिनसे का आयात बंद जमा करता है। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप अभी नहीं लगा रहा हूँ। यह बात जरूर है कि जो आरोप जनता सरकार पर लगाये गये उस की मैं कोशिश करूंगा कि आप सब को सफाई दे सकूँ। मैं एक चीज बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ और वह यह है कि आज वनस्पति में इस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन शायद माननीय मन्त्री जी को मालूम नहीं कि इस चर्ची का इस्तेमाल कबड़े पर भी होता है, कबड़े की साइजिंग के लिए किया जाता है बड़े पैमाने पर। आप ने चर्ची का आयात रोकने का एलान किया तो मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं घबरा गये हैं कि इस से वोट टूटेगा वरना बन्द करने का मतलब क्या था। कभी ज्यादा आता था, कभी कम आता था। मैं एक ही उदाहरण इस के बारे में देना चाहता हूँ और अगर मेरी बात गलत हो तो मन्त्री जी को हक है कि उस की सफाई कर दें। मैं ज्यादा लम्बाई में न जा कर हिन्दुस्तान में जब से जानवरों की चरबी का आयात शुरू हुआ, पिछले पन्द्रह वर्ष के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूँ। मेरे पास जो आंकड़े हैं वह सन 1966 से हैं। मेरे पास एक ग्राफ है, उस के तहत बता रहा

हूँ, सब से ज्यादा चर्ची का आयात पहले दौर में 68 में हुआ : 68 में मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक बुवकूफ ही कहेगा कि हिन्दुस्तान में जनता पार्टी की सरकार थी। तब करोड़-करीब 130 हजार टन का आयात हुआ उस के बाद 70 में करोड़ करोड़ 100 हजार टन का हुआ। 72 में करोड़-करीब 110 हजार टन का हुआ। जनता पार्टी बरसरे इक्त्दार आयी है 77 में, 78 में — 78 से 80 के दौरान जनता पार्टी का समय कहा जा सकता है। आयात हुआ 60 हजार टन का। अगर आंकड़े गलत हों तो बता दीजिये, मैं करीब करीब बता रहा हूँ, 60 का 62 हो सकता है, 58 हो सकता है।

श्री रामानन्द यादव : जो लाइसेंस जनता पार्टी की रेजीम में दिये गये (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम : पूरी बात सुनो।

श्री रामानन्द यादव : लेकिन यह बात मत भूलिये कि जनता पार्टी ने जो लाइसेंस दिये थे उसी से आज भी मंगा रहे हैं।

श्री लाडली मोहन निगम : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बुद्धिहीनता को क्या कहूँ। 72 के लाइसेंस से 77 में कोई नहीं मंगायेगा। रामानन्द जी मैं आप की इज्जत करता हूँ, सुना करो। मुझे इस बात का फक है कि सन 80 में हिन्दुस्तान में इस का सब से कम आयात हुआ, करीब वह हुआ है 15 हजार टन। अब आप यह भी कह सकते हैं कि क्यों कम हुआ या ज्यादा हुआ। जैसा मैंने शुरू में कहा था, जब हिन्दुस्तान में तेल के दाम, जिस का इस्तेमाल दूसरी चीजों में भी होता है, साबुन बनाने के काम में होता है, बीसीयों चीजों में होता है, जब उन के दाम बिलकुल नीचे हो गये तो स्वाभाविक था कि आयात कम हो जाय। जब 21 रुपये किलो का तेल हिन्दुस्तान में 8 रुपये, 9 रुपये बिकने लगे तो कौन इस को मंगायेगा। मैं व्यापार मन्त्री जी से चाहूंगा कि यह भी बतायें कि हिन्दुस्तान में जब-जब भी

जानवरों की चर्बी का आयात हुआ है उस वक़्त क्या दाम थे आन्तरिक तेलों के। तब हम को समझ में आ सकता है वरना कह देने से भूत आया, भूत आया, कोई फायदा नहीं ठीक है जनता पार्टी के जमाने में कुछ चीजों को उन्होंने ने खुले लाइसेंस में डाला। मैं आप को एक बात और बता देना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान में जब से आयात शुरू हुआ, बाहर की चीजों पर मुनहसिर करना—मैं इशारा करना चाहता हूँ—पी०एल० 480 किस ने शुरू किया? क्या जनता पार्टी ने शुरू किया? और उसके क्या क्या परिणाम हुए इस पर किसी बहस की जरूरत नहीं। जब से खान पान की चीजों को इम्पोर्ट करने का दरवाजा खुला है तब से ही यह सारा मामला चल रहा है। जो माल बाहर से आता है उस में दामों में कुछ न कुछ हाथ बिकने करने की गुंजाइश रहती है, जिस को कहते हैं ग्रीजिंग आफ दि पाम्स। तो मैं यह नहीं कहता कि व्यापार मन्त्री जी यहां बैठे हैं, सब राजा हरिश्चन्द्र हैं और किसी को भी लालच नहीं होगा। तो यह सारा शब्दों का जाल-फँसाव हुआ करता है। कभी उसे एनीमल टैलो कह दिया और कभी उसे शुद्ध टैलो कह दिया। मुझे इस का पता नहीं कि दुनिया में कोई बीफ टैलो नाम की कोई चीज है या नहीं। असल में यह है या नहीं इस का पता एक ही तरह से लगाया जा सकता है कि किस देश से कौन सी चर्बी मंगायी जाती है। कनाडा से अगर आप चर्बी मंगाते हैं तो वहां गाय खायी जाती है इस लिये वहां से गाय की चर्बी आयेगी। अमरीका से अगर आप मंगाते हैं तो वहां सुअर लोग ज्यादा खाते हैं इसलिये वहां से सुअर की चर्बी आयेगी और अगर आप आस्ट्रेलिया से मंगाते हैं तो वहां से भेड़ की चर्बी आयेगी जिस को आप मटन टैलो कहते हैं। लेकिन जब जानवरों की चर्बी मिल कर आती है तो क्या किसी प्रकार का ऐसा यंत्र है कि जिस से यह साबित किया जा सके कि यह बीफ टैलो है या नहीं है? मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा। जहां तक मुझे पता है, यह मामला मिलावट का है और प्रिवेंशन आफ

[श्री लाडली मोहन निगम]

एडल्टेशन एक्ट के पन्ने 94 की तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिस में ईडेबल फैट्स के बारे में कहा गया है। उस की धारा 10 को मैं कोट कर रहा हूँ कि अलग अलग चर्बियों के पता लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्योंकि स्पेसिफिक टैस्ट का नारा बहुत लग रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा स्पेसिफिक टैस्ट आप ने किया जिस से फलानी चीज में बीफ टैलो मिला। जब तक यह नहीं करोगे तब तक मैं समझता हूँ कि दोगली बात करोगे : इस में लिखा है :—

"Beef fat means fat obtained from beef. It shall have a saponification value varying from 193 to 200. After the test the value varies from 35 to 46.

"Mutton fat means mutton obtained from the guts of the sheep. It shall have a saponification value varying from 193 to 200 and the other value varies from 34 to 46.

"Goat fat means rendered from the fat of the goat and it shall have a saponification value varying from 193 to 196 and the other varying from 36 to 40."

चर्बियों के लिये किसी चीज का पता लगाने के लिये आइडिन टैस्ट ही हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने तरीके का टैस्ट कानून के तहत है उन से किसी भी आइडिन टैस्ट से इस का पता नहीं लग सकता। दोनों तरीके बराबर हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ने यह स्थापित करने के लिये कि यह बीफ टैलो है कोई स्पेसिफिक टैस्ट किया है और अगर किया है तो वह क्या है? ऐसा होने पर ही यह मामला साफ हो सकता है मैं जानता हूँ कि टैलो टैलो है। दस चीजों का हो, सब मिला कर एक जगह इकट्ठा कर के बेचा जाता है तो पता लगाना सम्भव नहीं रह जाता है। और अब तक विज्ञान ने बहुत तरक्की की है लेकिन अगर दस तरह की चर्बियां मिश्री हों तो पता लगाना कैसे सम्भव

होगा कि उस में किस किस की चर्बी है? और यही आधार होगा जिस से कुछ साबित हो सकता है।

अब मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ रामानन्द जी की बात पर, कि जब जनता पार्टी के समय में खुला लाइसेंस दिया गया तब उसके बाद क्या हुआ? ओपन जनरल लाइसेंस के सम्बन्ध में जो नीति शायद साया हुई उसके तहत जो नियम बने, उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ—

"Unless otherwise specified against the relevant items, import under OGL will be allowed only to actual users..."

SHRI A. G. KULKARNI: That is the point.

SHRI LADLI MOHAN NIGAM: "Import under OGL only to actual users registered with the DGTD and State Directors of Industries for use in their own industrial units..."

इसमें यह है कि अगर मेरे पास एक कारखाना है और उसमें उसका उपयोग होता है तो उस कारखाने की जितनी क्षमता है उसके लिए उतनी ही मैं मांग कर सकता हूँ। इस पर कोई बैन नहीं है। लेकिन ये जो महिलायें चिकनाई का इस्तेमाल करती हैं, इसमें सुन्दरता कितनी आती है यह तो अलग बात है, लेकिन चर्बी के साथ सुन्दरता जुड़ी हुई है, चाहे मनुष्य की चर्बी हो या जानवर की हो। क्या चीज ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता नहीं। मैं तो जो बाजार में मिलता है वही इस्तेमाल करता हूँ।

श्रीमती उषा मल्होत्रा : क्या कह रहे हैं आप? किसकी चर्बी की बात कह रहे हैं। महिला समाज के लिए आप क्या कह रहे हैं। सब को पता है ये तो ताली बजाने वाले हैं। ... (व्यवधान)। इनको क्या पता औरतों का।

श्री लाडली मोहन निगम : मैं मोहतरमा की बात को तस्लीम करता हूँ कि औरतों

के बारे में जो मेरा ज्ञान है वह इनका दिया हुआ है। ... (व्यवधान)

श्रीमती मोनिका दास : निगम जी, हिम्मत है, तो जोर से बोलिये। ... (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम : मेरा जो कुछ ज्ञान महिलाओं के बारे में है वह आप लोगों का ही दिया हुआ है, इसके अलावा मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने नीरस बहस को रसमय बनाने की कोशिश की।

उपसमाध्यक्ष महोदय, जो माल आता है उसके कोड होते हैं। व्यापार मन्त्री जी मुझे बता दें यदि कोड नहीं होते हैं तो। श्रीमन्, राज्य सभा में 15-11-82 को एक प्रश्न इस बारे में पूछा गया था, उसके जवाब में आपने कहा था कि सन् 1978-79 में 33214 टन, 1979-80 में 8394 टन 1980-81 में 29 हजार टन और 1981-82 में 58 हजार टन चर्बी का आयात हुआ। यह आपके मन्त्री जी का कहा हुआ है रामानन्द जी। ये झूठ बोल रहे हैं तो इन पर प्रिविलेज हो जाएगा। उन्होंने जवाब में यह भी कहा है—

“These figures relate to the description of items covered by the Indian Trade Classification Code...”

इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन का कोड है। जरा मुझे बताइये कि बौफ का कौन सा कोड है। मैं आपसे साफ जानना चाहता हूँ। (समय की घंटी)

श्रीमन्, मैं कोई सतही बहस नहीं कर रहा हूँ।

उपसमाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : सतही बहस का सवाल नहीं है, वक्त का सवाल है। ... (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम : आप जानते हैं सारे मुल्क में हंगामा खड़ा हो

रहा है। जनता को बहवदों के लिये थोड़ा टाइम दीजिये। ... (व्यवधान)

उपसमाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : लोगों को बेहबूदों के लिये मेरे पास बोलने वालों की लम्बी लिस्ट है : आप समाप्त कीजिये : 3.00 P.M.

श्री लाडली मोहन निगम : मैं यह कह रहा हूँ कि इंडियन कोडिफिकेशन के तहत जो भी आयात हुआ है उसका कोड नम्बर, 414023 था। कहीं भी बौफ का कोड नम्बर नहीं है। अगर वह बता देते तो पता लग सकता था। आप जानते हैं कि व्यापारी किन के साथ खेलते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो पुर्तगाली गुलामों की जगह रही है। जब सरकार बदलती है तो उनके साथ अपना मुखौट बदल कर ही जाते हैं। मेरा तो या कहना है कि अगर आप इसको रोकना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि गाय के नाम पर व्यापार न होता एक ही तरीका है कि गाय को न काटा जाय। जब तक गाय कटेगी तब तक गाय को चर्बी का मशला चलता रहेगा।

एक बात और अदब से कहना चाहता हूँ कि वनस्पति का व्यापार दूसरे महायुद्ध की देन है। उस वक्त आप को याद होगा कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं ने नारा लगाया था कि आम धर्म में इसको मिलावट न हो सके इस के लिये इसको रंगीन कर देना चाहिए। लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया क्योंकि उसके लिये पैसा मिलता है। हाथ चिकने करने की संभावना जुड़ी रहती है। अगर आप इसको करने के लिये तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि खान-पान आदमी के व्यक्तिगत रुचि का सवाल है और रुचि के सवाल से ज्यादा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको पता है कि मिलावट सबसे बड़ा गंभीर अपराध है।

[श्री लाडली मोहन निगम]

मिलावट को लेकर लोगों ने क्या-क्या बातें उठाई हैं लेकिन उसको रोक नहीं पाये। अगर आप मिलावट को नहीं रोक सकते, स्वाभाविक है, नहीं रोक पायेंगे तो कम से कम एक कानून बना दोजिये वनस्पति में या किसी और चीज में चर्बी मिला रहेगा तो उस पर लिखा रहेगा कि इसमें चर्बी मिला हुआ है। जैसे कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। फिर भी जिसने पीना हो पी ले वह यह एक स्टेटचुअरी ला बना दोजिये। अगर हमारा मन है कि उस को खाने का तो हम खा लेंगे भले ही उसमें चर्बी मिला हुआ हो : जैसा आपने कहा कि जनता पार्टी ने इसे चलाया है, मैं यह कहता हूँ कि चाहे किसी ने किया हो जनता पार्टी हो या आपको पार्टी हो, इस देश में चर्बी का आयात होता है और होता रहेगा, हो सकता है कल आप चुनाव तक के लिए बन्द कर दें लेकिन इस का चलना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार है तो इस के लिये एक ही इलाज है कि बिनाबा जी के बताये रास्ते पर चली कि बन्द करो गो हत्या। फिर गाय की चर्बी नहीं मिलेगी। जब तब चर्बी बाहर से आयेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक बात और कहना चाहता हूँ कि सुअर की चर्बी का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मुझे जैसे आदमी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह बीफ टैलो है या क्या चीज है मंत्री महोदय बता सकें कि यह बीफ टैलो है तब मैं मानूंगा। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ इसको राजनैतिक मुद्दा बनाने की कोशिश मत करो।

श्री रामानन्द यादव : आप उनको क्यों नहीं कहते ?

Why don't you point out this to them?

SHRI LADLI MOHAN NIGAM; To whom?

SHRI RAMANAND YADAV; To the Alliance.

श्री लाडली मोहन निगम : आपने फिर यह बंद क्यों किया ?

श्री रामानन्द यादव : इस लिये कि आपको लाई को खत्म करना चाहते थे।

श्री लाडली मोहन निगम : यह बिल्ली फिर आ गई।

SHRI RAMANAND YADAV; You are also sailing in the same boat.

श्री लाडली मोहन निगम : मैंने कहा कि इसका राजनैतिक उपयोग मत करो। इसको ईमानदारी से करो इस में बड़ी बेइमानी है, लूप होल्स है। व्यापारी लोग सब जानते हैं। आपने कोड़ी फिकेशन नहीं किया। कोड़ी फिकेशन किया होता तो कोई मंगा नहीं सकता था।

एमीमल टैलो नहीं मंगा सकता। इस वास्ते मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका आप राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश मत करो, मिनिस्टर साहब सारी चीजों को, सारे तथ्यों को बता दें। जब मिनिस्टर साहब जबाब दें तो इन सारे तथ्यों का जवाब दें। तभी इस बहस का कोई उपयोग होगा, वरना जैसे बहस हुआ करता है वैसे ही बहस होकर रह जायेंगे।

DR. RAFIQ ZAKARIA (MaTiafash-tra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not propose to go into the various aspects of this problem because I assure the Commerce Minister will deal with them in his own Effective manner. But I agree with my friend, Mr. Ladli Mohan Nigam, that what we have to guard against is the political exploitation of this controversy which has a deep religious significance.

Sir, as a Muslim I feel as deeply about it as any Hindu because where religious sentiments are concerned, we must all be united that, nothing should be done which will hurt the feelings of our people.

And, it is from that point of view that I am looking at this problem. I would like to emphasise." Sir, that while this controversy has arisen, who ever might have been responsible for it, whoever was the guilty party, whatever action the Government has sought fit to take, they have taken it. What is worrying me is that we should not play "in this matter with the feelings of the consumers. After all, Sir, as the Commerce Minister in his statement has made it clear, the mischief has been done by certain unlicensed persons. The adulteration that has taken place, has taken place as a result of the mischief of certain individuals who have tried to misuse whatever licenses or other facilities that they were given. And, therefore, Sir, when I was in Bombay, many vanaspati manufacturers came to me rather frightened and asked me whether the Government was going to nationalise the vanaspati industry. And, I told them very frankly that it is not a question of the management or mismanagement by the vanaspati manufacturers. It is a question of restoring confidence among the consumers because it is their confidence that is sought to be shaken. And I said that if the Government felt that the only way to restore the confidence among the consumers was that the industry should be nationalised, then I did not see any reason why the Government should not take that step. Therefore, I told them that what they should try to do, instead of making representations to the Government, instead of trying to impress upon the Government that they did not do this and they did not do that, was to reach the consumers and try to find out as to whether there was really this kind of a situation as far as they were concerned. I asked them to send their representatives, take the assessment and survey and get to know the facts as to what they were. That would be the indication as to how deep this kind of controversy had gone among the people. And, one of the best ways, I said, to find out whether people had really been affected by this controversy, was by assessing whether there had been a decline in the sales of vanaspati. And I am happy to inform the House that from the facts and figures collected by these people, apart from what the

Commerce Minister has to say, it is clear that instead of there being a decline in the sale of vanaspati there has been, in fact, as far as the comparative period is concerned, a rise in the sale of vanaspati. That means that the media has been blowing up this controversy, despite the fact that certain interested parties have made use of certain mahants, religious functionaries and other sources to mislead the people.. (Interruptions).

उपसमाध्वक्ष (श्री संयद रहमत अली):

आपको बारी जब आयेंगे तब आप बोल सकते हैं। दूसरों के बोलते वक्त आप दखल देते हैं यह ठीक नहीं। उनको कहने दीजिये। जब आपको बारी आयेंगे आप तब कहिये।

DR. RAFIQ ZAKARIA: I can assure Mr. Rameshwar Singh that on this question, I am not at all speaking from any partisan or party point of view; I am subject to correction as far as my facts are concerned. I am putting the facts because I am sure Mr. Rameshwar Singh is as concerned as anybody else that the confidence and faith of the consumer— as far as these products are concerned— is not shaken, because you do not expect that a consumer should give up using vanaspati whatever might have been there, and it is from that point of view that I am looking at it. Therefore, I do not say: All right, if somebody committed a wrong, you should not take action against that person. I am only saying that fortunately for us, fortunately for the Government and fortunately for the Opposition who are I believe as concerned as anybody else with the interest of the consumer, that their faith in the product as such is not shaken despite all this propaganda that has been going on and that it has no effect; and I can place these facts and figures before the House and I tell Mr. Rameshwar Singh that if he finds that any of these facts or figures are not correct, I am prepared to apologise to the House, because I have tried to collect this data as objectively as possible. In fact, the data of production and despatches in respect of 91 vanaspati factories shows that between the period November and September the production and despatch for the current year 1982-83 is quite compara-

[Dr. Rafiq Zakaria]

ble in relation to the previous year 1981-82. Figures are here and if the House is interested, I can place it on the Table of the House with your permission. I do not know if this is permitted; I do not want to take more time of the House. The figures show that especially in the last 3 to 4 months, there has been a rise in the sale of vanaspati and that shows the commonsense of our common people that despite all that is going on, on the basis of various statements made by the Government and the various samples that have been taken and the detection made that there has been by and large no such adulteration of any kind. But that does not mean that in certain areas the propaganda has not worked. I want to make it clear. South is fortunately free from all this propaganda; also Maharashtra and Gujarat; but I find—and this is subject to correction by the Commerce Minister—that in U.F. and Bihar there has been certain effect as far as this propaganda is concerned, and I would urge upon the Commerce Minister to see that in some of these towns because of mahants, temples where it is said that 'prasad' and other things should not be given and all that, some effect has definitely been there with the result that there has been a decline in the sale of vanaspati. And the areas in U.P. are: Lucknow, Faizabad, Kanpur, Alfababad, Gorakhpur, Varanasi, Sultanpur, Gonda and Ayodhya.

In Bihar, they are Muzaffarpur, Darbhanga, Samastipur and Ranchi. This is, as I said, after the survey which has been made. And this has been the result of this kind of propaganda which has been made. Therefore, it is the duty of the Government to make concentrated efforts to see that their doubts and suspicions, specially, as far as these affected towns are concerned, are removed.

Secondly, I have had a talk with the Minister of Food and Civil Supplies and I have also told the Commerce Minister that as a result of this propaganda, there is a feeling among the people that they would much rather go in for vanaspati, packed vanaspati in 2 kg., 4 kg. and so

on as the price of this is higher than in the big tins and containers because there they could get the open thing, although the Ministry of Civil Supplies has restricted this to ten per cent of the sale. In the normal circumstances, I think, this would have been the right stand to take. But today, in view of this environment which has been created, it is necessary that this restriction is removed because the people want that whatever is given to them, if it is given in packed tins or packed boxes, this would be a big guarantee by the manufacturers and by this the manufacturers can also be held responsible. In the present atmosphere, there is also a danger, I would like to inform the Minister of Food and Civil Supplies, that somebody might try to do some mischief by trying to put in something even if it is allowed to be sold openly. Therefore, what is necessary is that this restriction is removed and I am sure, if the Minister of Food and Civil Supplies calls the manufacturers and tells them that they should better give it at the cost price, that Government would like them to reduce the higher prices which they are charging for these small tins and containers, in the present atmosphere, the manufacturers would be quite willing to co-operate with the Government. I would like the hon. Minister to take this into consideration in relation to the 5kg., 2kg. and* 1 kg. tins.

Lastly, I would like to say this without being misunderstood,—when I talked with these manufacturers,—there are 92 factories and more than 99 per cent of the manufacturers are Hindus and quite a number of them came to me—they said, they are much more deeply religious persons than the others. They asked me 'Do you mean to say that just for making some money, we are going to be guilty of this heinous crime?' Then there is another question which I would like the Minister of Commerce to bear in mind. These manufacturers told me that in their factories, more than ninety per cent of the workers are Hindus and they asked me 'Do you mean to say that they would tolerate our being a party to this?' They told me that whoever are the hon. Hindus have also assured them in this regard. Therefore, there is no question.

I am placing these facts before the House so that the consumers may know about it so that we can restore their confidence. I am not saying that their confidence has not been shaken. I am not saying that somebody has not played mischief. I am not saying that all the actions which should have been taken were taken. All this may be there. But today, what is important from the national point of view, is that we should restore the confidence of the consumers and for this reason, I would like the Minister of Commerce, fortunately for us, the Minister of Civil Supplies is also present here, to spell out what are the various steps which the Government propose to take because I thought that is the most important problem that we have to face. Action you will take, measures you will take, you will ban that and you will do many other things, but what exactly are you going to do as far as restoring confidence among the consumers is concerned?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Mr. Sukomal Sen.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Even in the case of vanaspali there were also some Hindus, they committed a crime. (*Interruptions*).

DR. RAFIQ ZAKARIA: Who is going to be guilty? There may be a black sheep. If we accept your thesis, that means all the Hindus who are in this trade, all the workers in this trade, are guilty. That is too much. There are black sheep in every community and surely they should be punished, but you cannot say that the whole mass, who are involved in this trade, is so inreligious or anti-religious. (*Interruptions*).

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): A hundred years ago a gentleman from Germany, called Karl Marx, said that if you touch all the edicts of the Papal bull there may be no objection, but if you touch his profit or property, there will be a revolt. I hope you are aware of that.

DR. RAFIQ ZAKARIA: I am sure, even Karl Marx will not say that because one Hindu was guilty, therefore, damn all the Hindus.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Religion is not the obstacle, that is what I want to say. (*Interruptions*).

SHRI RAMANAND YADAV: Karl Marx has become outdated. You do not restrict yourself to his ideology.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Mr. Ramanand Yadav, that means whatever is written in Bhagwad Gita. . (*Interruptions*).

SHRI RAMANAND YADAV: Bhag- * Was Gita is quite different. (*Interruptions*)

DR. RAFIQ ZAKARIA: In any case, adulteration is a State subject. I would like to know what Karl Marx or your Government in West Bengal has done about it.

SHRI RAMANAND YADAV: Mr. Chatterjee, you want to hang yourself with the ideology of Karl Marx.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Mr. Ramanand, please take your seat. Yes, Mr. Sukomal.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharashtra): They do not believe in a parliamentary democracy. (*Interruptions*). Why are you sitting in Parliament? If you are a Communist, you should not sit here because the Communists do not believe in a parliamentary democracy. (*Interruptions*). I am not objecting, I am trying to make you understand. (*Interruptions*).

DR. RAFIQ ZAKARIA: Should I tell my Marxist friend that if really this matter was in their hands, they would definitely have adulterated even beef tallow because they would like to see that everybody's religion is polluted? (*Interruptions*). Who are they to talk about this? They would exactly do the same thing what Mr. Jain did. Your Government would do the same thing. You would be the one to use tallow so that all the Hindu religion is finished.

SHRI K. MOHANAN (Kerala): It is not the question of Communists. It is the capitalists who would do anything.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): I won't allow anybody Yes, Mr. Sukomal Sen.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I am very sorry to say that the question of beef tallow has taken an unfortunate turn. In fact, it is basically the question of corruption, corruption of monstrous order, and that issue is now being given a different turn. Different questions are raised here. Different things are being said here, as to who is a Hindu, who is a Muslim... as if adulteration does not affect one community, or does not affect every community. Adulteration affects everybody, whether he is a Hindu, Muslim, Sikh or Christian. Adulteration or corruption affects everybody. The entire population of the country is affected by adulteration and corruption. So I view it as a question of adulteration and corruption.

It has been said that beef tallow was imported in this country when the 'anla i'arty was in power. They brought beef tallow under OGL. In fact, beef tallow was being imported in this country from before 1977. It was being imported for various purposes. It was being imported for manufacture of soaps and various other items. And now I find that last year—though the official figures are not available—about 1 lakh tonnes of beef tallow was imported into this country. My point is this, whether the issuance of OGL was right or wrong is a different question. But what was the Government doing when 1 lakh tonnes of beef tallow was imported last year? Did Government try to find out how the trading community was using the imported tallow? Was the Government keeping a watch on this issue whether it was being used in vanaspati and for the manufacture of soaps? Government was not keeping a watch. On the contrary, we find that when this Vinod Jain imported huge quantities of beef tallow and it was seized, instead of confiscating the entire stock of beef tallow that was imported, by this Vinod Jain, a fine was imposed on him and he was let free. Did the Government enquire whether this Jain had used it for the manufacture of vanaspati, or what he will do with this beef tallow, or what use he will make of this beef tallow? The Government did not enquire all that. On the contrary, a fine was imposed and he was left free. So the Government itself is going to indulge

in corruption. And now the issue has been raised as if it is a question of Hindus and Muslims. On this question, communal passions are being whipped up. There were some demonstrations here and there with cows as if sacrilege of Hindus was done by the import of beef tallow and mixing it for manufacture of vanaspati. In this way the whole issue is being given a communal turn. Now whether it is mutton tallow or beef tallow or pig tallow, mixing of this tallow for adulterating vanaspati is a crime. Even if mutton tallow is being mixed, it is a crime. If it is beef tallow that is mixed, it is a crime. It is a criminal offence on the part of the trading community and industrialists. But communal passions are being aroused through this issue. In our country, already communal tensions are there; communal conflicts are taking place; and we know that there are forces, national and international, who are trying to whip up communal tensions. This vanaspati issue has been raked up as another centre for further rousing these passions. Not only that, I find Government has come out with a statement that they have banned altogether import of animal tallow. Why? Why has a blanket ban been put. Beef tallow was being imported from 1977. It was being used for manufacturing soaps. Who in this country does not know that for soap manufacture, beef tallow is necessary. Now if somebody says that he did not know that soap is manufactured with beef tallow, then it is a shortage innocence. Everybody knows that beef tallow is used for making soaps and people of our country have been using soaps for a long time, knowing full well that beef tallow is mixed in soaps. Now the Government has come down with a blanket order banning the import of animal tallow. In fact, I find that the Government is also bowing down to the pressures of communal forces. They are yielding to communal passions or communal forces who are trying to raise communal tensions. It may be that some forces are there who are trying to woo the voters on communal lines, raising the issue of beef tallow, or pig tallow, or some other tallow. At the same time, I find the ruling party and the Government are not lagging behind. They are

not lagging behind. They have come up with a statement which is quite monstrous. Here they say, this extraordinary step was taken in deference to the sentiments of the people. What sentiments? It is adulteration, it is corruption. If beef tallow is mixed with vanas-pati, it is a case of adulteration and corruption. You should say that to fight this adulteration, to fight this corruption we have banned import of animal tallow. Then people would understand it. But you said, in deference to the sentiments of the people. It means you are fanning communal sentiments of the people, you are vying with communal forces and you are not lagging behind them. You are vying with the communal forces; that is the charge against the ruling party and the Government. As my friends were saying, it is not a question of Hindus or Muslims. Muslims do not eat pork and Hindus do not eat beef. But, for making money, for reaping profits, religion is no bar to the capitalists. I do not know whether Mr. Vinod Jain himself is a Hindu or a Jain. He is not a Muslim, he is not a Sikh, but he is importing beef tallow and mixing it with vanaspati, knowing fully well that this will be consumed by Hindu population as well as Muslim population and Sikh population. Wilfully he is bringing it. It means that for reaping profits, for squeezing money, he has no deference and he has no respect for religion. That is the way of capitalism in which we are living now. (Interruptions). . . Yes, for making money, you can do anything. I would appeal to the Government not to vie with communal forces. At the same time, from my party I would appeal to other friends also that this issue should be viewed in the correct perspective, as a perspective of corruption and adulteration. They should not fan communal passions, they should not bring out processions with cows and they should not perform yagnas and other religious performances so that Hindus who consumed this vanaspati feel that they are atoned, and they should not perform other religious rites. This has been done in northern India though in Bengal, I am proud to say, nobody is bothered whether beef tallow is mixed in it or not. They are bothered whether there is adulteration in vanaspati. But in some parts of northern

India I find that some religious performances were organised for the atonement of Hindus who have consumed such vanas-pati. And religious leaders themselves have been coming out with statements. It is my apprehension, it is my doubt that the ruling party themselves, the Government themselves, are bringing some religious leaders and getting injunctions from them that unintentionally if you eat some beef or beef tallow, it is not a crime, it is not something bad-which means feeding /it religious sentiments of the people. So I would request the Government as well as the other forces to stop this activity of fanning communal passions on this issue. However, I would appeal to all that we should fight this utter degeneration which is taking place at the top and percolating to the bottom.**

SHRI VISHAJIT PRITHVUIT SINGH: I take strong exception to Oris. . . (Interruptions) ... It should be expunged from the records.

श्री जे० के० जैन (मध्य प्रदेश) : श्रीमान्
ये जो चीजें हैं उनका कार्यवाही से कोई
संबंध नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) :
मैं देख लूंगा । श्री भागवत झा आजाद
अब डिबेट में इंटरवीन करेंगे, उसके बाद
बहस जारी रहेगी ।

श्री जे० के० जैन : उपसभाध्यक्ष
महोदय, मुझे आधा मिनट दे दीजिये, ।
मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि
हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को
इस की बड़ी चिन्ता है, तो मैं जानना चाहता
हूं कि 1979 में जो भी सरकार थी क्या
उस सरकार ने बीफ टैलों के उपर ड्यूटी
कम की थी या नहीं, यह मंत्री जो से
मैं जानना चाहता हूं ।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, in 1979, when Mr. Charan Singh was the Prime Minister, he had exempted beef tallow from duty.

**Expunged as ordered by the Chair.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Mr. Vice-Chairman, Sir, this debate has got two aspects: one, the adulteration of vanaspati with animal tallow; and the other, the import and other matter relevant thereto. The latter, my colleague, Shri Vishwanath Pratap Singh, will reply to.

The first part, adulteration of vanaspati with animal tallow, I would like to deal briefly. It is known, Sir, that vanaspati is produced from vegetable oils by a process. It is also known that in north India mostly it is a very cheap cooking medium for not only the middle class but also for the poor people. It is produced, as I said during the Question Hour, in 92 factories in this country which get licence from the Government. It is not that we just give them the licence and they produce as they like. Production is governed by the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 and another Order, Vegetable Oil Products (Standard of Quality) Order, 1975.

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है। जब कोई माननीय सदस्य बोलता है तो आप कह देते हैं कि उनके बीच में बाधा मत कीजिए। जब यह तय हो गया कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली): किसने तय किया है ?

श्री रामेश्वर सिंह : आपने ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : मैंने तय नहीं किया। मैंने उनको इजाजत दी है बोलने की।

श्री रामेश्वर सिंह : अगर इनको इंटरवीन करने की इजाजत है, ये मंत्री हैं, ये कर सकते हैं, तो हमें भी ऐज ए मॅम्बर, हम सदन के सदस्य हैं, हमको

भी मंत्री की बात पर इंटरवीन करने की इजाजत होनी चाहिए। हम भी इंटरवीन करेंगे।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली): यह तो प्वाइंट आफ़ आर्डर हुआ ही नहीं।... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : यह सवाल नोति का सवाल है, प्रिंसिपल का सवाल है। जब आपने तय कर दिया कि—जब डिप्टी चेयरमैन चेयर पर बैठे थे उन्होंने कहा कि पार्टीवाइज बोलेंगे। तो अगर मंत्री बोलेंगे तो हम भी इंटरवीन करेंगे। आप 12 बजे रात तक बहस चलाओ... (व्यवधान)

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Mr. Vice-Chairman, this House is governed by the rules which are laid down by this House. Under that rule, this discussion has arisen out of a statement by Shri Vishwanath Pratap Singh, who will reply in the end. The same rule provides that another Minister can intervene, but in no rule....

श्री रामेश्वर सिंह : आप बीच में कहाँ से आ गए। यह मामला हमारा कामर्स मिनिस्टर के साथ है। जब हमारा मामला कामर्स मिनिस्टर के साथ है तो भागवत झा जी कहाँ से आ गए ?

श्री भागवत झा अजाद : अब आप रिलार्ड सुन लीजिए।

Mr. Vice-Chairman, I will reply to this question. (Interruptions) I will reply to you now. Mr. Vice-Chairman, it should be known to the hon. Member that when a debate takes place in the House and matters are referred to which do not exactly pertain to the debate but to other Ministries, the Ministers are entitled to take part in the debate. And in this debate there are two major questions. (Interruptions) It only shows that the hon. Member does not want to face the facts.

What I was going to say is that in this country vanaspati is produced in 92 factories. They are not only produced under licence from the Government, but they are strictly under the vigilant control of the Directorate. And there are two orders of the Government, Mr. Chairman. One is the Vegetable Oil Product Control Order, 1947 and the other is the Vegetable Oil Products (Standard of Quality) Order, 1975. What are the meanings of these two orders? I will specify how there can be no adulteration in vanaspati. These two orders specify what the raw materials are that will be used in the production of vanaspati. These orders say that the raw materials to be used in the production of vanaspati can be cotton seed oil, soyabean oil, sunflower oil, water melon seed oil, maize oil, safflower oil, ruger oil, sal seed oil, sesame oil and palm oil. These are the raw materials which can be used in the production of vanaspati. Use of other things, even other oils, will be illegal, and they will be liable to prosecution. Animal tallow does not come anywhere at all. If anybody uses this, it is illegal, and he can be prosecuted. We have been told, or it is being told by some persons that adulteration has been made in the vanaspati. Some of the Members have said. "Let us know if there is adulteration, and if it is there, let us stop it." I also expressed the anxiety and concern of the Government. If there is any adulteration, we certainly are coming with a heavy hand and will come with a heavy hand to stop it. But the question is let us analyse whether there is adulteration in the production of vanaspati. I say that there has been no adulteration in the production of vanaspati. How do I say that? Why do I make this claim? I make this claim that 92 factories that are producing vanaspati in the country out of these raw materials are subject to strict control. Vigilance and vigil. We have the Directorate whose officers make regular visits to the vanaspati factories.

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह इंटरवीन कर रहे हैं।

इनका बयान है... आप बैठ जाइये
(व्यवधान)

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Why should I sit down?

श्री रामेश्वर सिंह : यह इनका बयान है। जो पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी थी उसमें कहा है कि इसमें मिलावट हुई है। मैं पढ़ देता हूँ।
(व्यवधान)

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Let me finish what I want to say. What I have to say, Mr. Chairman. Please try to understand.

श्री रामेश्वर सिंह : यह इनका बयान है। इसमें लिखा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली): जब आपकी बारी आयेगी तब बोलियेगा।

श्री रामेश्वर सिंह : जब कामर्स मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं तब यह क्यों जवाब दे रहे हैं। आप मुझ को भी इंटरवीन करने दोजिए। (व्यवधान)

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Mr. Vice-Chairman, it only shows that this hon. Member is not prepared to face the facts. He is only interested in rumourmongering in the country and trying to make political capital out of it. Be prepared to face the facts and reply me after that. Mr. Rameshwar Singh, please hear me. But what paper are you showing? I want to say, and I have said it earlier, that there has been no adulteration of vanaspati in the 92 factories in the country. Lest you should stand up again, I hurry to add, I have said, however, out of 50 raids by the Punjab Government, in two cases which I said in the question hour—you were sitting and I thought you had heard and understood it at Amritsar and Bhatinda there were five samples, out of 405 samples, which were detected as having tallow. I told this in the Consultative Committee meeting. The hon. Member does not read

[Shri Bhagwat Jha Azad]

and understand the things before intervening. So, I come to the joint again, Mr Chairman. I want to assure this House and the country that there has been no adulteration of vanaspati by any animal tallow in this country. How do I make this claim? I make this claim first there are possibilities, not only in vanaspati but in other things also, of adulteration. That is why Government makes laws. That is why Government keeps staff. That is why Government has the paraphernalia to check the anti-social elements. Which part of the world has not got antisocial elements, a couple or a dozen? Mr. Vice-Chairman, it will be an ideal and Utopian society in this country also if there will be no adulteration of vanaspati with anything, except the use of what I have prescribed under the two orders. We have field staff. What do the field staff do? The field staff very regularly visit the factories and draw samples. Samples of what? Samples of prepared vanaspati and also samples of the oils which are supposed to be used in the production of vanaspati in the factory. And we have got the most up-to-date, latest laboratory in Delhi where we analyse the samples. From January to October 1983, Mr. Vice-Chairman, in ten months, we have made 746 surprise checks and we have drawn 3,964 samples. That is what the Prime Minister referred to—about 4,000—in one of her speeches. And these samples have all been analysed in the most up-to-date, modern factory and we have not found a trace of animal tallow or adulteration in the vanaspati. Therefore, I can boldly say to this House and to the nation that there has been no adulteration of vanaspati by animal tallow in this country. But (when the question comes.... *(Interruptions.)*) I can give you facts and figures.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): Their Marxism is definitely adulterated. That you must know. *(Interruptions)*

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Forget about the CPI(M). For Marxism, religion is the opium of the people. They would not know what is opium, what is religion and what is adulteration. Therefore, you should not worry about them.

Therefore, what I am saying is that it is very evident and clear that if I make this statement to this House and to the nation that there has been no adulteration whatsoever even in one case in the 92 vanaspati factories in the country, I have got proof for it. I challenge the hon. Members who are making whispering campaign to produce one piece of evidence. But the question is... *(Interruption)* Please try to understand.

SHRI RAMESHWAR SINGH: *

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली):
श्री रामेश्वर सिंह जो भी बात कह रहे
हैं वह रिकार्ड पर नहीं आयेंगी ।

SHRI RAMESHWAR SINGH: *

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली):
श्री रामेश्वर सिंह जो भी बात कह रहे
हैं वह रिकार्ड पर नहीं आयेंगी ।

SHRI RAMESHWAR SINGH: *

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली):
आप जो यह पॉजिटिव लपज का इस्तेमाल
कर रहे हैं, क्या आप जिम्मेवारी से बोल
रहे हैं ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I would request the hon. Member to lend me his ears, not his mouth. Then he will appreciate and understand me better. If he will hear what I have to say, I think he will appreciate it. But the hon. Member is persistently creating trouble. He does not want the country and the House to understand the facts. That is the trick and manipulation. I am only saying about what Mr. Rameshwar Singh has said about the Consultative Committee.

*Not recorded.

How does this news come out? How has this adulteration been found in the country? What I am saying is that after vanaspati reaches the factory, it will go into the hands of traders and in the different States of this country they are distributed, they are sold. There, now, the Prevention of Food Adulteration Act comes into the picture which, like any other food article, tries to see that after the production stage there is no adulteration at the trader level. In this instance the Punjab Government made 50 raids and 405 samples were taken from various places in Punjab. Out of the 405 samples, 5 samples—2 in Arnritsar and 3 in Bhatinda, Bhatinda Chemicals!—were found to be adulterated with animal tallow. In Arnritsar vanaspati was found and at Bhatinda in the oil it was found. Around this has been woven the entire story of adulteration by certain vested interests in this country to harm or touch the sentiments, the religious feelings, of the people, I would like to have from the Opposition members, those who are saying all this. Come and tell me, here are the cases of adulteration either at production level which I am denying or at trader level, so that Government will certainly take action with a heavy hand. Government has a heavy hand to act. What I want to emphasise is, I support my contention that there has been no adulteration of vanaspati with tallow and also that this whispering campaign has not affected the people. They are wise enough to understand what some of the political parties, opposition parties, in this country, are up to. I am only quoting the production figures so that things will become clear to the House and to the country, whether this false propaganda has got any effect on the people. Certainly our people are innocent. They are simple. They are not that educated. Our literacy is only 39 per cent. Therefore, they are led to that as they were led to in family planning in 1977. But those days are gone now. They have realised how by hook or by crook some people are trying to come to power. No more such political propaganda and whispering campaign will affect the people. This I am supporting by my facts and figures. In 1981-82 we gave the factories 6,02,000 tonnes imported oil. They produced vanas-

pati 9,03,000 tonnes. They had taken out despatches 8,92,000 tonnes in 1981-82. Now I am giving figures of 1982-83. We have given them 6,88,000 tonnes imported oil. It should be known by the honourable Members that we are giving at present 85 per cent of imported oil for the production of vanaspati to these 92 factories. Compared to 6,02,000 tonnes the year before, this year we have given them 6,88,000 tonnes. Production is 8,90,000 tonnes of vanaspati. What is the despatch? 8,82,000 tonnes. It will be more because there are still two months. So these are the figures of production and offtake, and they belie the contention that the people have been in any way misled by the gentlemen who are creating this kind of scare in the country. They have not been led up to that. Therefore, I say that these gentlemen cannot give me evidence. They are only shouting and doing this sort of campaign. These political parties have got a good army, trained army, with half pants and half shirts. They go on saying, 'Look, there is vanaspati, there is adulteration,' and so on. But that has not been affecting the people. People know what it is, I am also a Hindu. I also feel that. I am not an atheist like the CPM. I am not saying about the manufacturers. The greatest check against adulteration is done by the workers in the Vanaspati manufacturing factories. No worker will tolerate it and he will not allow any manufacturer to bring animal tallow into the factory premises. The workers in the factory are not less Hindus or less Muslims or other communities. They will burn the factory rather than allowing the manufacturer to bring it in his factory. This is apart from our vigilance which we exercise at our level. I have given the figures and the facts. I would challenge hon. Members to produce their figures. Why should there be an enquiry by a Supreme Court Judge? Why appoint him? Give me your *prima facie* facts. These are my facts which go to prove that there is no adulteration. What are your facts? I said that Punjab Government came down with a heavy hand on the traders, and out of 400 samples only two samples of vanaspati were found to be adulterated. And they are being prosecuted in the court and they have been charged.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

And you say that, there is large-scale adulteration. There are anti-social elements and unscrupulous elements in every society. One swallow does not make a summer. These two cases of adulteration do not go to show that there is adulteration in Vanaspati in this country. From time to time people are caught, they are charge-sheeted and prosecuted. What I want to tell hon. Members and the people of this country is that we exercise strict vigilance and take prompt action and I am happy to say that so far there has been no such case of adulteration in vanaspati. All the scare that has been made is politically motivated. Some of the parties in the opposition want to use this as political propaganda. Our people are innocent and simple. But as I showed from the figures they are not misled by this propaganda. Of course we on this side have always the duty to go to the people and explain the facts to them as the Prime Minister said. Let them come and see how much vigilance we are maintaining and how Vanaspati is being produced. There has been no adulteration.

There was one suggestion from Dr. Zakaria. At present we are making available ten per cent of the total production in small packs. The Finance Minister also asked about this. Why not increase this percentage? This has been the suggestion. I shall certainly consider this suggestion. Only point is that there shall be some increase in price because when you put it in polythene bags, it costs more. Still we will try to do it and ask the manufacturers to do it without profit. We will try to do something and increase the percentage.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप यह साफ कर दीजिए कि पहले कितना बनता था ? कुछ गलतफहमी यह है कि यह पहले 10 प्रतिशत से ऊपर पैकेज में बनता था ?

श्री भागवत झा आजाद : यह पैकेज पहले इतना था । पैकेज 10 प्रतिशत इसलिए है, हम तो ज्यादा इनक्रीज कर

दें लेकिन समस्या यह होती है कि इससे थोड़ी कीमत बढ़ जाती है । इसलिए हमने अभी यह काम किया है । अब हमने एक किलो का भी और आधा किलो का भी पोलि पैक बनाने का विचार किया है । अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है । We have taken the decision and we will do that also.

Mr. Nigam has given another suggestion. I accept Dr. Zakaria's suggestion. Mr. Nigam's suggestion was: Why don't we write on the vanaspati container that it does not contain tallow? I would not do it negatively. But I will do it positively. I will write on the container that this Vanaspati contains these things' and indicate all that, whether it is sesame oil or cotton seed oil etc. I will have it indicated in the same way as it is written on drugs.

This, Sir, is the suggestion. So, I accept the suggestion and I will make a positive writing on it so that it will also help. Therefore, Mr. Vice-Chairman, Sir, in the end. I would say—about the import part our friend will deal with the issue—that so far as adulteration is concerned, we have no evidence so far excepting the couple of cases where at traders' level anti-social and unscrupulous elements were found and only in those cases some of the honourable Members, some of the parties in the Opposition in the country, have tried to hurt the feelings of the people. Mathur Sahib was telling, "Don't play with the sentiments of the people." Who are playing with the sentiments of the people, I or you? You are playing with the sentiments of the people. You should know this. About the Shudh Vanaspati, Sir, today there was a question regarding adulteration. If the Jain Shudh Vanaspati firm has committed a crime in importing under the import regulations, that is being dealt with and we shall not leave it, whether it is done by a shudh fellow or an ashudh fellow, whoever has done it in this country, and we are taking action against him and we shall not deter from taking any action either under the Prevention of

Food Adulteration Act or the Import Control Act. Our friends have asked, "Why don't you totally ban it?". Well, you are all hardened Marxists. Possibly you thought, as you have said about West Bengal, that there has been no problem to be dealt with. There has been no problem in West Bengal. As a matter of fact, Sir, I would say that no State Government excepting one has complained and that one is from Bihar, it is in Ranchi, where a tin consisting of tallow—it was no adulteration, but only tallow was there—was found. I have sent them despatches, telegrams and reminders and I have told them and I have requested them through letters and telegrams, "Please keep vigilance. Try to use the Prevention of Food Adulteration Act. Have raids and checks. Draw samples and have them analysed and see that at the traders level, after the vanaspati leaves the production side, the factory, there is nothing.". No State Government has so far informed us that in their State there has been any adulteration and when I say, "No State Government", there is not only the Congress (I) Government, but there are non-Congress Governments also, controlled and run by the Opposition parties as well. It is a fact that the State Governments have had nothing to say in this. This fact that they have nothing to say in this, this fact that production has been as much as there has been offtake, this fact that our regular checking is there where almost four samples are taken every month from every factory, all these facts clearly prove that there has been no adulteration at all and adulteration is only in the minds of those people who monopolise themselves, who call themselves Hindus especially. We are as well Hindus in this country and we know what the sentiments are and what sentiments are there. Therefore, Sir, I would like to assure this House and the country and the people that the Government is taking all precaution. AH precaution means what I have analysed. I have tried to increase the frequency and I have done it from the 1st of January, when this whisper was not there, till October and I will not relent in this case and I will have every check possible and I will not hide from the House and the country if I find any adulteration, be-

H32 RS—9

cause I must come and speak to the House and the people that there are antisocial elements like the two cases which have been found out and they will be dealt with. Therefore, I think it would be good for the country and for the people if these honourable Members and the parties, who are trying to make out of it a political propaganda, deter from this. They are harming the people by depriving them of a very cheap and hygienic cooking medium. By this they are only helping the lobby which tries to push up the prices in this country of oil. They are doing this on the one hand. On the one-hand they are charging the Finance Minister saying that they are increasing the prices of oil and, on the other, by their action they are pushing up the prices, pushing the prices upwards. I would only request them to consider it coolly. Whenever such cases come to our notice, certainly we shall be one with them in dealing with them, giving them the heaviest punishment that is possible under the Act and if more is required, more will be done by the Government. With these words, Sir, I would like to say that this has been just a camouflage, a political propaganda with an eye on the elections—I don't know when they are coming, but they are trying this from now. I have said that it would not be beneficial for them. They are harming the people also whom they promised to serve, and for whom they took the oath to serve. Therefore, with these words, I say that let country be assured what there will be no adulteration, because the two cases that have been found out they are being dealt with by the Punjab Government, and if any new cases come up we will deal with them also.

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): On a point of order. The assurance given by the hon. Minister for Civil Supplies no doubt will relieve the anxiety of the people from this controversy. But I want to seek some information. Two consignments of mutton tallow were received in the Madras harbour when this controversy was raging in the north. I want to ask where these consignments were sent and how...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Your name is there. You can ask this when you speak, not now.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: A large quantity has been imported, mutton tallow or whatever it is. I want this clarification.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: This will be replied to by the Commerce Minister. (Interruptions)

श्री पी० एन० सुकुल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर बहस चल रही है वह बड़ा नाजुक मसला है और बड़ा गम्भीर मसला है। यह बड़े दुख की बात है कि हमारे विरोधी दल के साथी लोग इस मसले को एक राजनीतिक मुद्दा बना कर हमारी सरकार के खिलाफ कीचड़ उछालने में लगे हैं, लोगों को बरगलाने में लगे हैं। आज धर्म की आड़ ले कर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है हमारे भाजपा के साथियों द्वारा, लोक दल के साथियों द्वारा, विरोधी दलों द्वारा ताकि आने वाले चुनाव में उन को कुछ वोट ज्यादा मिल जायें। ऐसी सम्भावना उन्हें है, ऐसी आशा उन्हें है।

हमारे मंत्री श्री साहब ने, माननीय सिंह साहब ने सब ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है और बीफ टेलो, गाय की चरबी यहां लाने के लिए कौन जिम्मेदार है। गाय की चरबी का खुले रूप से आयात करने की जनता सरकार ने छूट दी थी, ओ. जी. एल. के अन्तर्गत इस को लाया गया था और तत्कालीन कामर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री मोहन धारिया का जो बिल्टन में बयान छपा है अगर आप उस को पढ़ें तो उन्होंने बड़ी सफाई से इस चीज को कहा है, हाँ, हम ने यह छूट दी थी, हम ने 77-78 में 25 हजार टन बीफ टेलो मंगाया था।

श्री रामेश्वर सिंह : कहाँ कहा ?

श्री पी० एन० सुकुल : जिन पढ़िये 5 नवम्बर का।

श्री रामेश्वर सिंह : उन का ओरिजिनल लैटर हमारे पास है।

श्री पी० एन० सुकुल : मैंने अखबार पढ़ा है, वह मैं आप को सुना रहा हूँ। अगर वह सही नहीं है तो अखबार में उनका कन्ट्रिब्यूशन आना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह अंग्रेजी नहीं जानते, आप इन को बता दें।

श्री पी० एन० सुकुल : अंग्रेजी नहीं जानते इसी लिए तो मैं हिन्दी में बोल रहा हूँ ताकि हमारे नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस के साथियों के विभाग में हमारी बात अच्छी तरह से आ जाये। आज धर्म की आड़ ले कर एक दूषित वातावरण तैयार किया जा रहा है हमारे देश में। मैं तो इसे बड़े शर्म की बात समझता हूँ। बहुत छोटे स्तर पर हमारी राजनीति चल रही है। बहुत छोटे स्तर पर हमारे भाजपा के साथी, लोकदल के साथी—दोनों साथ हो गये हैं, यह चुनावी गट-बन्धत है, शहर में वोट भाजपा दिलायेगी, देहात में वोट लोकदल दिलायेगा। और बचा छूटा बीफ टेलो से शायद कुछ ज्यादा वोट उन को मिल जायें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 1967 में क्या हुआ। 67 में यही हमारे तत्कालीन जनरल के लोग जो आज भी भा जा पा में हैं गो-बध बंदी के नाम पर चुनाव लड़े और उन्होंने कहा कि गो-बध बन्धी होना चाहिए और उस चुनाव के पहले आंदोलन हुए और न जाने क्या क्या हुआ और उस चुनाव को वे लोग जीत भी गये। उन को बेनीफिट ग्राफ हाउट जनता ने दिया। 67 में उन को थोड़े से ज्यादा बोट मिले...

श्री रामेश्वर सिंह : 9 राज्यों में सरकार बनायी ।

श्री पी० एन० सुकुल : लेकिन उस का परिणाम क्या हुआ ? उन को उस समय थोड़े ज्यादा बोट मिले लेकिन वही लोग जब यहां आ कर डई साल के लिये जनता सरकार में बैठे तो वह भूल गये कि गो-बध बंदी को मुद्दा बना कर हम ने 67 का चुनाव लड़ा था । यह लोग धर्म को बचायेंगे ? या यह देश को बचायेंगे ? देश की आजादी की लड़ाई में जिस पार्टी का एक भी आदमी जेल नहीं गया हो, जो इतनी नयानक लड़ाई लड़ी गयी उस का क्या है । आज तो सब लोग एम एल ए और एम पी बन जाते हैं, ओ जी एल से चाहे जो मंगा लो या दूसरी तरह से मंगा लो, लेकिन आजादी की लड़ाई में एक भी उन का आदमी जेल में गया हो तो वह बता दें । (व्यवधान) बाजपेयी जी एप्रुवर हो कर गये थे और इस के मायने हैं कि उन को देश की चिन्ता नहीं थी । उन लोगों ने गो बध बंदी को चुनाव का मुद्दा बना कर चुनाव लड़ा और जब सरकार बनायी 9 प्रदेशों में तो क्या एक भी प्रदेश में आप ने गो-बध बंदी की ?

श्री रामेश्वर सिंह : केन्द्र गिरने ही वाला था उस समय ।

श्री पी० एन० सुकुल : मैं आप को बता रहा हूं रामेश्वर सिंह जी, और मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि यह लोग

धर्म की रक्षा नहीं कर सकते । न वह गो को बचा सकते हैं और न धर्म की रक्षा कर सकते हैं । 68 में लखनऊ नगर महापालिका का चुनाव लड़ा गया और उस समय वहां जनता पार्टी सर्वोत्तम थी । जनसंघ नाम था उस का । उस समय की एक घटना मुझे याद आती है जिस को मैं बता रहा हूं । उस 68 के लखनऊ के चुनाव में एक वाडें था कनीसी । वहां चुनाव के एक दिन पहले एक गाय काट दी गयी । इतिहास साक्षी है और बाद में पता चला कि जनसंघ के लोगों ने उसे कटवाया । यह धर्म को बचाने वाले हैं ? उन्होंने गाय को कटवा दिया ताकि हिन्दू वर्ग समझे कि मुसलमानों ने यह किया है और बोट हम को आ जायं । तो मैं आप को बता रहा हूं । आप इस का पता लगाइये ।

श्रीमती विजया राजे सिधिया (मध्य प्रदेश) : आप ने कोई बात एक बार भी आज तक सिद्ध कर के दिखायी है ? (व्यवधान)

श्री हंसराज भारद्वाज : मैं डाकुमेंट देता हूं । अगर मेरी बात साबित न हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । अगर बाजपेयी जी एप्रुवर साबित न हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । (व्यवधान)

श्री मनुभाई पटेल (गुजरात) : पुरानी बातों को ले कर आप बहकाने की बातें कर रहे हैं ।

श्री पी० एन० सुकुल : आप को नहीं मालूम कि विरोधी पक्ष में कैसे

[श्री पी० एन० सुकुल]

कैसे लोग बैठे हैं। आप को नहीं मालूम है।

श्री मनुभाई पटेल : मैं भी आ गया हूँ इस में।

श्री पी० एन० सुकुल : मेरी बात पर श्रीमती विजया राजे जी ने एतराज किया। मैं आप के माध्यम उन से कहना चाहता हूँ कि इस बात का वह पता लगा लें जहाँ बात मैं उन से कह रहा हूँ वह अखबारों में छपी है या नहीं।

श्रीमती उषा मल्होत्रा : मैंने एक फोटोस्टेट कापी दी है डाकूमेंट की। उस का पता लगाइये कि वह डाकूमेंट ठीक है या नहीं। (व्यवधान)

श्री पी० एन० सुकुल : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा बहुत सा समय लोग नष्ट कर रहे हैं। आप इस बात का ख्याल रखियेगा। मैं यह कह रहा था कि एक धृणित स्तर पर उतर कर इस मिलावट का नाम लेकर यह जानते हुए भी अपने हृदय में कि इस बीफ टैलों का इंपोर्ट कराने वाले हम ही लोग हैं, फिर भी जनता में भ्रम पैदा करके हमारी सरकार के खिलाफ एक गलत प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। इसका कोई नतीजा उनके हक में निकलने वाला नहीं है क्योंकि हमारी जनता बड़ी समझदार है। हमारे वाणिज्य मंत्री ने बारबार स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनकी नीति क्या थी और हमारी नीति क्या है। एक और लिब्रलाइज्ड इंपोर्ट, उदारतापूर्वक बीफ टैलो इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई और टैलो मंगाया गया और दूसरी ओर हमारी सरकार ने उस पर टोटल बैं लगा रखा है। अब आप

ही जनता को बता दो कि आप क्या थे और हम क्या हैं। अब भी आप यह बतायेंगे कि हमारी नीति क्या है ?

When there is a total ban and total restriction on the import of beef tallow, what more do you have to say? You have nothing to say. You want only to beat the political drum. That is all. And that is not going to be of much consequence, I may tell you.

हमारी सरकार ने टोटल बैं कर दिया है। तो आप अब और क्या चाहेंगे, क्या कहेंगे ? इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि हमारी सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है, इंदिरा गांधी की सरकार ने, हमारे वाणिज्य मंत्री की सरकार ने हमारे झा साहब की सरकार ने कोई ऐनीमल टैलो इंपोर्ट नहीं किया, बीफ टैलो की ही बात नहीं है। श्री मोहन धारिया ने दूसरी ओर इसको जस्टिफाई किया है कि होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश में जानवर मरते हैं, गाय भैंसें मरती हैं तो उनका टैलो इस्तेमाल किया जाता है तो हम बाहरी टैलो क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं ? हमारी सरकार ने इस पर टोटल बैं किया और जनता सरकार की यह नीति थी, उनका यह विश्वास था, उनकी यह धार्मिक भावनायें थी और हमारे देश की धार्मिक भावनाओं का वह इतना आदर करते थे जो आज इतना हल्ला कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा कि यदि कहीं गुंजायश हो सकती है या कहीं शिकायत आई तो तुरन्त उस पर टोटल बैं लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि इंदिरा गांधी जी की जो वर्तमान सरकार है, वह हिन्दू, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का समादर करने की भरसक कोशिश कर रही है और इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास

कर रही है कि किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे विरोधी दलों की पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है यह कहने के लिए। हमारे माननीय मंत्री जी का जो बयान है वह बिल्कुल साफ है। उन्होंने कह दिया है कि—

The regulatory provisions pertaining to the import of animal tallow have been activated.

दूसरी ओर जो इन्फार्समेंट मशीनरी है वह कितनी तेजी से काम कर रही है, इसका भी उन्होंने हवाला इसमें दे दिया और यह कहा है कि जहाँ भी शक की चुंआयश है वहाँ पर हमने उनका इंपोर्ट बंद कर दिया है और ऐसी फर्म्स 146 हैं जिनके साथ यह कड़ाई की जा रही है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। 11 मामलों में सी० बी० आई० ने बाकायदा कम्प्लेंट लाज कर वी हैं। हम ऐक्शन ले रहे हैं, हम जागृत है जनता की भावनाओं के प्रति।

इसीलिए मैं अपने विरोध पक्ष के साथियों से कहना चाहूँगा विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के साथियों से कि हल्ला मचाकर आप लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। इस पर जबरदस्ती कीचड़ उछालने की कोशिश न करें वरना वह कीचड़ आपके ही ऊपर आयेगी तो आपका ही मुँह काला होगा, आपका ही शरीर मँदा होगा और चुनाव में जो आप चाहते हैं कि इससे शायद वोट मिल जायेंगे, मैं समझता हूँ कि स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद भारत के जो लोग यह समझ जायेंगे और आपके वोट कट जायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय वाणिज्य मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूँगा कि जहाँ तक सम्भव हो, वनस्पति को इसें शायल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्दर जरूर लाया जाए। यह जरूरी आइटम है। हर गरीब इसका प्रयोग करता है, इसका इस्तेमाल करता है। इसलिए इसे ऐसैं शायल कमोडिटीज ऐक्ट के मातहत इसको लाया जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गरीबों के हक में हमारे देश के, इस वनस्पति का मूल्य जल्दी जल्दी न बढ़ने पाये ताकि हमारी गरीब जनता इसका उपभोग कर सके।

श्रीमती विजया राजे सिंधिया : वाइस चेयरमैन साहब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार इस विषय पर प्रकट करूँ। परन्तु आज सुबह से मैं यह देख रही हूँ कि इस आगस्ट हाउस के अन्दर जिस प्रकार की ट्रीट जेनरेट की जा रही है उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। जो सबसे बड़ा उच्च हाउस है ला मेकिंग बाबी है वहाँ हम लोग एकत्रित होते देश की जनता के हित के लिये, उनको भावनाओं का आदर करने के लिये और उसके अनुरूप यहाँ कानून बनाकर, ट्रेजरी बैंच द्वारा उसके अनुरूप शासन आदि चलाया जाता है। इस प्रकार देश की जनता के हित की भावनाओं को लेकर हम यहाँ एकत्रित होते हैं। परन्तु मैं देख रही हूँ कि देश की जनता की, टेक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई किस तरह से बरबाद होती है। हमारा मकसद एक ही है चाहे वह अपोजिशन हो या ट्रेजरी बैंच हो। हमारा मकसद यह है कि जो गरीब जनता है, करोड़ों जनता दुखी है उन लोगों की जो मुसीबत है उसको दूर करना है। उनकी जो भावनाएं हैं उनको हम सेफगार्ड करते हुए

श्रीमती विजया राजे सिधिया]

उनका संरक्षण करते हुए उनको स्वाभिमानी जीवन बिताने के लिये हमें एक ऐसा रास्ता निकलना है जिससे हम सुगमता के साथ आगे बढ़ सकें। मैं देख रही हूँ कि सुबह से शाम तक इस तरह से उलझे रहते हैं और देश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है, पसीने की कमाई है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बड़ी नम्रता के साथ ट्रेजरी बैच में बैठे हुए अपने मित्रों को बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ कर अर्ज करता चाहती हूँ कि यह प्रक्रिया जो वर्षों से हमने पार्लियामेंट के अन्दर शुरू कर दी है वह ठीक नहीं है। अपोजिशन कोई बात कहता है इसलिये अपोजिशन की बात को गिराना है यह ठीक नहीं है। अगर कोई अच्छी बात अपोजिशन कहता है उसको भी सुनना नहीं उसका भी सत्ताधारी पक्ष अपोज करना चाहता है। इस तरह की भावना को लेकर अगर हम डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं...

श्री हरिसिंह भगुवावा महिडा (गुजरात): क्या गलत बात का जवाब नहीं देना चाहिये ?

श्री पी० एन० सुकुल: क्या जनता सरकार नहीं करती थी... (व्यवधान)

श्रीमती विजया राजे सिधिया : बाद-विवाद होना चाहिये यह मैं मानती हूँ। परन्तु बाद-विवाद कब होना चाहिये जब कि हम किसी बात पर डिफर करते हों। परन्तु यहां तो डिफर नहीं हो रहा है। केवल एक दूसरे को प्वाइंट आउट करने जा रहे हैं। मुझे खुशी होती। आपने टैलो को बंद करने की घोषणा कर दी इसके लिये मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे आशा ही नहीं, विश्वास लिये हुए हूँ कि चुनाव के बाद भी इस चीज को जारी रखा जायेगा। यह खाली चुनाव तक न रहे।

श्री हरिसिंह भगुवावा महिडा : चुनाव कहां हो रहे हैं ?

श्रीमती विजया राजे सिधिया : आगे जब भी होंगे। आप लोगों के हाथ में है। आपके वॉस के हाथ में है। जब चाहे आप चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। इसके लिये तैयारी हो रही होगी। हमें यह बताया गया है कि चुनाव के लिये तैयारी हो रही है। यानी आप चाहते हैं कि अगर हमारे देश की जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे उस पर भी हम न बोलें तो फिर हमारा पार्लियामेंट में रहना बेकार है।

एक माननीय सदस्य : ठेस किसने पहुंचाई ?

श्रीमती विजया राजे सिधिया : आपने कहा कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है इसलिये मैं आपसे नम्रता के साथ अर्ज कर रही हूँ कि राजनीतिक फायदा उठाने की बात कहां नहीं हो रही है। यह असल में देश की जनता की भावनाओं पर ठेस लगी है उसके कारण हम को बोलना पड़ रहा है।

क्योंकि हम भी देश के कुछ अंश को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जो यहां पर हैं या लोक सभा में हैं हम सब देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको भी कहने का अधिकार है और हमको भी डिफेंस करने का अधिकार है। अगर देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो इस सरकार के सामने उस मसले को लाएंगे सरकार के सामने रोज करेंगे। यह

हमारा अस्तित्व है, अधिकार है। अगर देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो वह मामला सरकार के सामने लाया जाएगा। आपने टैलो का आयात बन्द कर दिया, यह अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जब आप अच्छा काम करेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे और अगर बुरा काम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। जो ठीक काम है उसको हम ठीक कहेंगे। इस मामले को आप छोटा मामला मत समझिये। यह काफी गम्भीर मामला है। जो लोग इसके अपराधी हैं उनको आप फाँदी से फाँदी सजा दीजिये। इसमें कोई सिझंक की बात नहीं है... (व्यवधान)। मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : जब आपकी सरकार ने इसका आयात किया तो उस वक्त आपने दुःख क्यों प्रकट नहीं किया... (व्यवधान)।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन् मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अब खामोश बैठे हुए हैं इनको रोक नहीं रहे हैं... (व्यवधान)।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : मैं तो घंटी बजा रहा हूँ लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : ये लोग इस तरह तमाशा कर रहे हैं... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : अब आप बैठ जाइये।

श्रीमती विजया राजे सिधिया : मैं यही कह रही थी कि हमारे देश की जनता के कुछ मान-विन्दु हैं। हमारी भारतमाता, हमारी गऊ माता, इस प्रकार के हमारे

मान-विन्दु हैं। हमारे देश की जनता जनार्दन का इन पर विश्वास है... (व्यवधान)

अगर आप राजमाता बनाते हैं तो ठीक है, धन्यवाद। मैं यह कह रही थी कि हमारे जो मान-विन्दु हैं उन्हीं के चारों ओर हमारा राष्ट्रीय जीवन भी चलता है। हम देश की जनता की भावनाओं को अवहेलना नहीं कर सकते हैं। चाहे हम अपोजीशन में हों या शासन में हों हमें देश की जनता की भावनाओं का आदर करना होगा। इस मामले में देश की करोड़ करोड़ 90 प्रतिशत जनता इन्वोल्व है। हिन्दू और मुसलमान दोनों इसमें शामिल हैं; दोनों के जजबात को इससे ठेस पहुंचेगी है। जिन लोगों ने इस में फायदा उठाया है उनको आप सजा दीजिये अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं... (व्यवधान)।

श्री हाशिम रजा आबदी इलाहाबादी (उत्तर प्रदेश) : आपने अभी हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के जजबात की बात कही। मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी मुसलमान मौलवी ने इस कंट्रोवर्सी में पड़कर अपने आप को इन्वोल्व नहीं किया है... (व्यवधान)।

†[شری ہاشم رضا عابدی الہ آبادی]

(अंतराष्ट्रीय) : آپ نے ابھی ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے جذبات کی بات کی ہے - میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان مولوی نے اس کنٹروورسی میں پڑ کر اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا..... (مداخلت)

श्री अब्दुल रहमान शेख (उत्तर प्रदेश) : मौलवी सब मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं... (व्यवधान)।

†[] Transliteration in Arabic script.

†[شہری عہدالرحمن شہیح (انپروڈیو):

مولوی سب مسلمانوں کو ریپریزنٹ
نہیں کرتے ہیں..... (مداخلت)

श्री हाशिम रजा अब्बो इलाहाबादी :
आप हिन्दुओं को बात कह सकते हैं,
लेकिन मुसलमानों के जजबात के साथ
खिजाड़ मत कोजिये... (व्यवधान)।
आप मुसलमानों के जजबात के साथ नहीं
खेल सकते हैं... (व्यवधान)।

†[شہری ہاشم، رہا بدی ال آبا و:

آپ ہندوؤں کی بات کہہ سکتے ہیں
لیکن مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ
کھلواڑ مت کیجئے..... (مداخلت)
آپ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ
نہیں کھیل سکتے۔]

श्री अब्दुल रहमान शेख : अब
आपको मुसलमानों की दुकानदारी नहीं
चलेगी... (व्यवधान)।

†[شہری عہد ال من شہیح : اب

آپ کی مسلمانوں کی دوکانداری
نہ چلے گی..... (مداخلت)]

श्रीमती विजया राजे सिधिया: महोदय,
मैं अपने साथियों से हाथ जोड़कर अर्ज
करना चाहती हूँ कि देश को आज कम्युनल
बातों पर लड़ाई करने, झगड़ा करने का
समय नहीं है। हमें एक होकर इस
देश को एकता और यूनिटी को बनाना है।
इसलिये आज जब ऐसा मसला आया
है, जिस पर हिन्दू क्या और मुसलमान
क्या, सब एक हो रहे हैं, इस एकता को
हमें टूटने नहीं देना चाहिए। जहाँ भी
हमारी धार्मिक भावनाओं या आस्थाओं पर
प्रहार होगा जनता अगर ऐसा महसूस
करेगी तो उसको यहाँ पर आकर
प्रदर्शित करेंगे इसको यहाँ पर प्रदर्शित
करते हुए बताते हुए हमें कोई गुनाह नहीं
किया है, यहाँ मैं अर्ज करना चाहती हूँ।

†[] Transliteration in Arabic script.

मुझे खुशी है कि हमारी मंत्री महोदय ने
आश्वासन दिया है कि यह जो टूलो है,
इसका आयात करना बन्द कर दिया
गया है। मुझे आशा यही है कि यह
हमेशा के लिये हुआ होगा। क्योंकि बहुत
मे भाई यह बता रहे हैं आर्थिक दृष्टि
से भी इसको देखना पड़ेगा। परन्तु
आप जानते हैं कि यह देश एक
भावुक देश है, भावना-प्रधान देश है, इस-
लिये आप देश की जनता की भावनाओं
को कुचल नहीं सकते हैं। हमारी इन
भावनाओं का जो बैकग्राउण्ड है, उसका
विश्लेषण करने के लिये इस समय समय
नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहती हूँ
कि यह केवल एकानामिक बात ही नहीं
है बल्कि धार्मिक बात भी है। इसलिये
मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि यह जो मसला
है इसको हमें एकजुट होकर हल करना
है। जो गलत बातें हुई हैं इसके लिये
जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए।
इसको केवल चुनाव का मसला बनाने
के ब्याल से नहीं करना चाहिए बल्कि हम
लोगों के जो सेंटोमेंट्स हैं हमारी जो
पवित्र भावनायें हैं उसको सामने रखते
हुए इस पर विचार करना है। मैं इस
आशा और विश्वास को लेकर कहना
चाहती हूँ कि आप भी देश की जनता को
रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इस बात का
ध्यान रखें। यही आशा और विश्वास
प्रकट करते हुए जो कुछ आज तक गलत
हुआ है, वह दुबारा नहीं होना चाहिए
उस गलती का रिपेटिशन नहीं होना
चाहिए। चाहे इस पक्ष के लोग हैं और
चाहे उस पक्ष के लोग, उन्हें जो गलत
बात है वह गलत कहना चाहिए और जो
सही है उसे सही कहना चाहिए। हमें
इस दृष्टि से देखना चाहिए। हमें
छोटी छोटी बातों को न देखते हुए
देश की एकता की दृष्टि से देखना चाहिए।
आज के युग का यही तकाजा है कि हम
लोग इस बात को और इस दृष्टि से

विचार करें ताकि इस देश के जनता के सेंटोमेंट्स और उनकी धार्मिक भावनाओं के ऊपर ठेस न पहुंचने पायें। जनता जनार्दन, गौ-माता और मातृ-भूमि (व्यवधान)... आप कितना ही हंस लें, यह भारत का सेंटोमेंट है इस पर हंसने से कुछ नहीं बनेगा... (व्यवधान)... गौ-माता, जनता जनार्दन और भारतमाता ये तीनों हमारी नीति के विषय हैं और इन तीनों विषयों को लेकर ही देश को प्रगति कर सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि हमारी मुस्लिम जनता भी हमारे साथ है, क्योंकि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। भारत की महानता इसी में है, उसकी जो संस्कृति है वह यह है कि वह किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती है। सहिष्णुता हमारी सबसे बड़ी चोज रही है। इस सहिष्णुता के नाते हम अपने मुस्लिम भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इससे हिन्दू-मुस्लिम एकता मजबूत होगी और इस तरह से देश आगे बढ़ेगा और इस दिशा में हम सफल होंगे। इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) :
श्री रामेश्वर सिंह।

श्री रामानन्द यादव : महोदय, इनसे पूछा जाय कि क्या वे बनारस में गंगा स्नान करके आये हैं क्या ? क्या वे गंगा में स्नान करके पवित्र होकर आये हैं... (व्यवधान)...

SHRI VISHVAJIT PRITHVJIT SINGH: We are appreciative of Mr. Rameshwar Singh. He should appreciate that we appreciate him and that is why we are applauding him before he has spoken. I would request him for only one thing. In the course of his speech, could he kindly clarify

(व्यवधान) ठीक है हिन्दो में पूछ लेता हूँ। मेरे प्रिय मित्र रामेश्वर सिंह जो मैं अपनी तरफ से मांग करता हूँ कि वे हम को यह बता दें कि यह जैन शुद्ध वनस्पति जो है उसका आर० एस० एस० के साथ क्या लिंक था और कैसे था। अगर यह हमें जरा समझा दें तो हम बहुत मशकूर होंगे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस दिन इस सवाल को रज किया था और जिन कम्पनियों को लिस्ट दी थी मुझे बेहद खुशी है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्य सम्भालने के दो तीन महीने बाद ही यह सवाल खड़ा हुआ और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो स्टेप उठाया उस पर मेरी कोई शिकायत नहीं है (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) :
जरा उनको बोलने दीजिये।

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे शिकायत नहीं है। एक ही मेरी शिकायत है। इस सवाल को आज भी मैं राजनीति से हट कर के सोचता हूँ (व्यवधान)

श्री हंसराज भारद्वाज : यह बात गलत है। यह बात लोक दल वाले नहीं उठाते लेकिन आर० एस० एस० ने कह दिया (व्यवधान)

श्री अब्दुल रहमान शेख : यह बहुत संजोदा मामला है और इस संजोदा मामले को पेशों से मुन लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि आप हम पर रहम करो और अपने पर तथा देश पर भी रहम करो। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता

[श्री रामेश्वर सिंह]

हूँ जिससे कि देश खतरे में पड़े, देश में कोई ऐसा वातावरण पैदा हो जिससे आपको और हम को भी परेशानी उठानी पड़े। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को शुद्ध रूप से सोचता हूँ। इस कांड के पीछे इस घटना के पीछे मैं यह मानता हूँ कि गैर-इन्सानियत का काम किया गया है। जिन लोगों ने भी इस काम को किया है उन्होंने इस काम को गैर-इन्सानियत के तौर पर किया है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष भला होगा हमारी बात आप 10 मिनट सुन लें। हम को नहीं बोलने देंगे तो इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह फैसला देश करेगा। लेकिन हमें बोलने देंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, देश का भी कल्याण हो जाएगा, और मेरा भी हो जाएगा। आपसे मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। मैं कुछ ठोस बात करना चाहता हूँ। एक तो जो हमारा संविधान है उस संविधान ने हमें यह आश्वासन दिया है कि हम इस देश में जो लोग रहने वाले हैं किसी भी नागरिक के किसी के धर्म पर किसी भी तरीके से कुठारघात नहीं होने देंगे। हर धर्म के लोग इस देश में अपने धर्म का पालन कर सकेंगे और उसमें सरकार उनकी मदद करती रहेगी और उनको किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुँचने देंगे। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : कौन सी धारा में है ? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : अगर मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो उससे क्या फायदा होगा ? (व्यवधान)

श्री हरि सिंह नलवा (हरियाणा) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। श्री रामेश्वर सिंह ने कहा है कि मेरी बात न सुनेंगे तो क्या फायदा होगा ? फायदा यह होगा कि

इनकी गलत बात सुन कर हमारा दिमाग गलत नहीं बनेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : नलवा जी, यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। मैं पूरे हाऊस से दरखास्त करता हूँ कि हाऊस की कार्यवाही ठीक ढंग से चलने में कोअप्रेट करें। वक्त बहुत कम है। आप रामेश्वर सिंह जी को सुनें। मैं उनसे भी तैयारी रखता हूँ कि वे भी कोअप्रेट करने का जज्बा अपने में पैदा करेंगे। वराएकरम कोई मोअजिब मैम्बर मदाखलत न करे।

श्री रामानन्द यादव : श्रीमान, यह किताब तो बिखा देते हैं, लेकिन धारा कोट नहीं करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : कंस्टीट्यूशन आफ इंडिया उन्होंने बतलाया है, धारा डूट लें। आप परेशान क्यों हैं ?

श्री रामेश्वर सिंह : सवाल इस बात का नहीं है कि किस गवर्नमेंट ने इसको मंगवाया है या किसने नहीं मंगवाया है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री रामेश्वर सिंह : इस विवाद को हम लोग करेंगे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मेरी तथा और पांच आदमियों की एक कमेटी बना दें, हम लोग विचारों का आदान-प्रदान कर लेंगे। हम किताब लाये हैं—हम एक-एक किताब इम्पोर्ट पालिसी की लाए हैं। एक किताब यह है और यह भी इम्पोर्ट पालिसी की ही किताब है। हम इसे पूरी तरह से पढ़ना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं करेंगे।... (व्यवधान)

श्री रामानन्द यादव : जो लड़का पढ़ने में तेज नहीं होता है, अपने पठन का जो बोरा होता है, उसमें बहुत सा कचरा रख कर बहुत बुरा होता है।... (व्यवधान)

SHRI K. MOHANAN: This is not fair, Sir. Mr. Rameshwar Singh, I know, is fully competent to defend himself. But this is not proper, this is not fair.

श्री रामेश्वर सिंह : अगर यह नहीं चाहते हैं, तो मैं वहाँ आकर के बैठता हूँ और वह बहुत गलत बात होगी। तब यह आपको बड़ा मंहगा पड़ेगा। . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली): आप अपनी तकरीर जारी रखिये।

श्री रामेश्वर सिंह : अगर यह हाऊस की सीरियसनेस को खत्म करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझको वहाँ आकर के बैठ जाना पड़ेगा और फिर बात इसी में तय हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता था और क्या नहीं कहना चाहता था। . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED ALI): Order, order please.

श्री रामेश्वर सिंह : अगर आप हमारी बात को डिस्टर्ब करने को कोशिश करेंगे, तो मैं वहाँ बैठने के लिए आता हूँ। . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली): आप अपनी तकरीर कीजिए।

श्री सत्यपाल मलिक : हाऊस ऐसे नहीं चलेगा। . . . (व्यवधान)

श्री अब्दुल रहमान शेख : अगर कलिंग पार्टी की तरफ से यही रवैया जारी रहेगा, तो मुझे बेहद अफसोस है। जब एक मेम्बर इधर से बोल रहे हैं, तो उधर से सारे बोल रहे हैं। इन्हें शुरू तो करने दें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यदि एक वक्ता बोलता है, तो बीच-बीच में तो डिस्टर्ब करते हैं कभी-कभी, लेकिन उन्होंने प्रारम्भ ही नहीं किया और पहले ही ऐसे . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली): उन्हें बोलने दीजिए . . . (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : बड़ा मंहगा पड़ेगा . . . (व्यवधान) उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक-एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। अभी हमारे साथी, जकरीया साहब चले गये। मुझे बेहद अफसोस है कि हमारे साथी बोलते हैं और बोलने के बाद चले जाते हैं। दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

जकरीया साहब ने कहा है कि वनस्पति का प्रोडक्शन, सेल बढ़ा है—इसके बावजूद बढ़ा है। मैं नहीं जानता कि उनके पास कौनसी रिपोर्ट है। मेरे पास जो कागजात हैं, मैं उनको पहले सुनाना चाहूँगा।

यह वनस्पति एसोसिएशन जो है वह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मिल चुकी है। उसका बयान है कि 30 प्रतिशत, जब से यह टैलों का सवाल आया है . . .

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह मुझ से नहीं मिली है।

श्री रामेश्वर सिंह : उसका बयान है कि 30 प्रतिशत प्रोडक्शन घटा है। . . . (व्यवधान) आप जवाब दे लीजिएगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ—मैं बात तो रखूँगा ही, लेकिन एक-एक करके मैं पहले रख लूँ। सरकार कहती है कि मिलावट हुई है, लेकिन एक-दो टीनों में हुई है। मैं कहां कह रहा हूँ कि दस लाख टन जो प्रोडक्शन होता है वनस्पति का, उसमें हुई है। मैंने कब कहा, किससे कहा हम लोगों ने, हम लोगों ने कहा है कि मिलावट इस देश में इतनी चरम सीमा पर चली गई है कि खाद्य पदार्थ में भी अब मिलावट होनी शुरू हो गई है। शुरू ही नहीं, खाद्य पदार्थ में मिलावट इस तरह से हो रही है जिससे कि इंसान की जिन्दगी खतरे में है।

[श्री जनेश्वर सिंह]

उपसमाध्यक्ष महोदय, मैं इसका कुछ विवरण रखना चाहता हूँ। यह टैलो होता क्या है? चाहे वह टैलो, अमरीका से आता हो, चाहे कनाडा से आता हो, चाहे ब्राजील से आता हो, टैलो, टैलो है, वह जानवरों की चरबी है। आप आश्चर्य करेंगे कि जो जानवर मर जाते हैं, जिन के अन्दर कीड़े पड़ जाते हैं, जिन में हाथ लगाने की गुंजाइश नहीं होती—विदेशों में तो प्लास्टिक लगा कर उस को छूते हैं—लेकिन हमारे देश में, गंगा के किनारे का मैं रहने वाला हूँ, जब जानवर मरा हुआ बहता है तो जो भाई चमड़ा निकालते हैं वह चरबी निकाल कर ड्रम में भर कर बाजार में बेचते हैं। वह चरबी चाहे वनस्पति में मिलायी जाती हो, चाहे खाद्य पदार्थों में मिलायी जाती हो, चाहे व्यवस्था में मिलायी जाती हो, वह मिलायी जाती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में करीब करीब 60 करोड़ लोगों में 55 करोड़ लोग धर्मावलम्बी हैं और उन में भी—ग्रांफड़े हमारे पास नहीं हैं—मांसाहारी और शाकाहारी बराबर-बराबर होंगे। मैं आप से अर्ज करूँ कि हमारी बहुत सी बहिनों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा, बहुत सी बहिनें विधवा हो जाती हैं, हमारी मां विधवा है, हमारे पिताजी नहीं हैं, वे छः-छः, आठ-आठ घंटे पूजा करती हैं, वह स्वप्न में भी नहीं सोचती हैं कि हमको कोई ऐसा खाद्य मिलेगा जो हमारे पूजापाठ पर असर करेगा। हमारी बाइफ या हमारी बहुत सी बहिनें एक दूसरे का छुआ पानी नहीं पीतीं, खुद लाती हैं, उन को यह मिला कर खिलाया गया। यही नहीं हमारे बहुत से साधु-सन्യാसी जो जंगलों में घूमते हैं, जो नदियों के किनारे बसते हैं, गांवों में रहते हैं, पूजापाठ करते हैं, जो अन्न नहीं खाते, शुद्ध रूप से फल खाते हैं, सिध डे का आटा खाते हैं, धी मंहगा है इस लिए वनस्पति में बना कर लोग खिलाते हैं, उन साधु-

सन्त्यासियों ने अपनी जिन्दगी लगा दी है धर्म में, हो सकता है कि उन की कल्पना झूठी ही हो, हो सकता है उस धर्म से कुछ न निकलने वाला हो, लेकिन उन की उस धर्म के प्रति आस्था है, वह कभी सोच नहीं सकते—हमारे जे० के० जैन भाई बैठे हैं, जैनी महात्माओं का मैं आदर करता हूँ जो मुंह पर पट्टी बांध कर चलते हैं कि कोई कीड़ा न चला जाय, उन को भी आप ने नहीं बरखा। मैं भाई विश्वनाथ प्रताप जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस को बँन कर दिया। लेकिन उन्होंने पहले बँन क्यों नहीं किया। लोग कहते हैं कि जनता पार्टी के रेजोम में दुप्रा। मैं कहता हूँ कि आप अपोजीशन में बैठे हुए थे, आप ने क्यों नहीं रोका। आपकी सरकार 32 वर्ष से थी (व्यवधान) '84 में मेरा टर्म खत्म हो रहा है। हो सकता है कि मैं इस सदन में न आऊँ, हो सकता है आ भी जाऊँ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी पीड़ा को देखिये जो सरकार 32 वर्ष हुकूमत में हो वह सरकार अपोजीशन में आयें और दो साल के लिए जो सरकार में आए वह दुनिया भर के पाप कर के जाय, दुनिया भर का वितंडा करे, देश को रसातल में ले जाये और आप उसे रोक नहीं पाये तो आप से निकम्मा कौन है। इन्हीं कारणों से—जनता गवर्नमेंट की अकर्मण्यता, जनता गवर्नमेंट की आपसी कलह का ही परिणाम था कि एक्सोल्यूट मेजरिटी की सरकार धराशाही हो कर चली गयी। उस सरकार को भी क्रिटिसाइज करने का, उस सरकार के खिलाफ लड़ने का श्रेय मुझे है। मैं इस सदन में उस सरकार के खिलाफ लड़ चुका हूँ। मैंने मोरार जी भाई से कहा था इसी सदन में कि अगर उन की सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी और

रोज वे लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो वह आप की सरकार 30 दिन भी नहीं चलेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : अब आप सक्जेक्ट पर आ जाइये। बहुत समय हो गया है।

श्री रामेश्वर सिंह : तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बड़ा सेंसिटिव मामला है। यह मामला मामूली नहीं है। मैंने उस गवर्नमेंट को भी कहा था और आप 80 में हुकूमत में आ गये तो आप ने यह क्यों नहीं किया? 1983 में इस को कब रोका, जब 17 नारीख को 18 कंपनियों की लिस्ट हम ने आप के सामने रख दी। यह चर्चा चल रही थी महीनों से और भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सदन में भी कहा था कि 11 या 12 हजार या 30 हजार टन टैलो आया है। हो सकता है कि उन के जरिये से यह बात टल गयी हो, और मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मगर जब इस सदन में 18 कंपनियों की लिस्ट पेश कर दी, उन के नाम दे दिये, टेलीफोन नम्बर दे दिये और उस में आप की सब से बड़ी कंपनी है एस० टी० सी०, जो सब से ज्यादा रिस्पॉसिबिल कंपनी है उस कंपनी के द्वारा भी लाखों टन माल आया है। यह भी लिस्ट हम ने पेश कर दी। मुझे माफ करेंगे यह कहने के लिये कि एस० टी० सी० ने अपने को इस में क्यों नहीं रोका?

एक सवाल मैं और कर रहा हूँ। जब आप को धर्म में विश्वास है, जैसा कि हमारे भाई ने कहा है और मैं उन की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। आप ने ठीक कहा कि मुसलमान इस झगड़े में नहीं हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ

कि... (व्यवधान) आप चेयर पर बैठे हैं? मैं आप से जानना चाहता हूँ कि अगर आप को पता चल जाय कि इस साबुन में सुन्धर की चरबी है जिस को आप शरीर में लगाते हैं तो क्या आप उस को छुएंगे एज ए मुसलमान? जहाँ तक मुस्लिम धर्म का सवाल है, मुस्लिम धर्म को मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं इस बात को अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि (व्यवधान)

श्रीमती मौनिका दास : आप हिन्दू के पास जा कर कुछ कहते हैं और मुसलमान के पास जा कर कुछ और कहते हैं। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : दो मिनट में अब आप मुकम्मिल कीजिए।

श्री रामेश्वर सिंह : मुझे 5 मिनट और दे दीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : ठीक है।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि इस देश के करोड़ों लोग गाय को माँ के रूप में देखते हैं। भाई विश्वनाथ प्रताप जी से पूछना चाहता हूँ कि आप की औरत गाय को माँ के समान समझती है या नहीं? मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जो सदन में बैठे हैं और या वे जो सदन के बाहर हैं कि वे सुन्धर का नाम लेना भी पाप समझते हैं या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप ने साबुन बनाने के लिये इस को मंगाया। अब मैं साबुन को डिस्कस कर रहा हूँ...

एक माननीय सदस्य : आप साबुन लगाते हैं या नहीं?

श्री रामेश्वर सिंह : 1926 में हिन्दुस्तान में साबुन का प्रोडक्शन कम होता

[श्री रामेश्वर सिंह]

था। रेह और रोठे से यहाँ का काम चलता था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और आजाद जी नोट कर लें कि 1926 में ब्रिटेन की एक कंपनी सननाइट साबुन बनाती थी...

श्री कल्पनाथ राय : लक्स लक्स। सबरे लक्स को उन्होंने कोट किया था। उन्होंने लक्स की बात कही थी। (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कल्पनाथ जी, आप को यह शोमा नहीं देता।

श्री रामेश्वर सिंह : उस कंपनी ने जब हिन्दुस्तान में अपना साबुन भेजा तो उस के दिमाग में 1857 की बात थी। उस ब्रिटेन की कंपनी ने जो साबुन यहाँ पर भेजा उस साबुन पर लेबल पर लिखा रहता था कि कोई इस साबुन में यह साबित कर दे कि इसमें चरबी मिली हुई है तो उसको एक हजार पाँड का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस देश में स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने इसका गलत प्रयोग किया। मैं भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे खत का जवाब दिया। मैंने उनको लिखा कि आपने टैलो साबुन बनाने वाली फैक्टरियों को दिया, वह कोई बच्चे नहीं हैं, ये कोई मोनिका दास नहीं हैं, ये कल्पनाथ नहीं हैं, ये लोग अरबों करोड़ों में खेजते हैं, देश के पूँजीपतियों का यहाँ पर कंट्रोल है। ये क्या आपसे कहते कि हम इसे साबुन में नहीं मिलायेंगे? क्या वह नहीं जानते हैं कि इस देश में करोड़ों करोड़ लोग हैं। आपने उनको लाइसेंस क्यों दिया। अगर दिया तो उसमें प्राविजन क्यों नहीं रखा कि अगर आप उसमें चर्बी मिलायेंगे तो उसके लेबल पर लिखेंगे कि इसमें टैलो मिला हुआ है। क्यों नहीं लिखा

गया कि इसमें चरबी की मिलावट है, जिसको इस्तेमाल करना होगा वह करेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 31 अक्तूबर को जो चिट्ठी लिखी थी, जिसमें इनके दस्तखत हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो मरे हुए, सड़े हुए जानवर हैं, इनको कड़ाहों में गरम किया जाता है और हड्डियाँ जो इकट्ठा होती हैं मरे हुए जानवरों की उनको गरम कड़ाहे में खोलते हैं और उनका रस निकालकर पीपों में भरते हैं और वह कल्पनाथ राय जी को पिलाते हैं। यही नहीं, मामला यही समाप्त नहीं होता। भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, आप हिम्मत से काम लीजिए, मैं जानता हूँ कि आप हटाये जाने वाले हैं क्योंकि कोई दूसरा मंत्री होता तो घूस लेकर छोड़ देता, लेकिन कम से कम आपने हिम्मत तो की। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) : आपका वक्त खत्म हो गया रामेश्वर सिंह जी। आप खत्म कीजिए।

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ। इस देश में यह तो साबित हो गया कि डालडा में, साबुन में, घी में गाय की चरबी की मिलावट है। चाहे एक पीपे में है या एक लाख पीपों में। वही अधिकारी है जिसने लाइसेंस दिया, वही जांच करने वाला है। ये लाखों रुपया घूस लेते हैं और घूस लेकर उनको छोड़ देते हैं। कोई एक लाख रुपये लेता है तो कोई एक लाख पैसा लेता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, विटामिन ए और डी होने की जो कंपनियाँ

मान्यता दे देंगी वह कंपनियां शुद्ध वनस्पति का सर्टिफिकेट ले लेती हैं। विटामिन ए और डी तभी होगा जब उसमें टैला मिलाया जाएगा। इसलिए जंगल कंपनीज जो भी वनस्पति बनाती हैं चाहे वह टाटा की हों, विडला की हों या मोदी की हों, सब में चरबी की मिलावट है। एक भी वनस्पति कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट न हो। मैं प्रणव मुकर्जी व श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि आप उसके लिए एक संसदीय कमेटी बैठकर जांच कराइये। मेरे पास प्रमाण हैं। मेरे पास 285 कंपनियों की लिस्ट है। 285 कम्पनियों में साबुन के निर्माता, तेल के निर्माता, डालडा के निर्माता, दवा के निर्माता हैं। यहां तक कि डाबर के च्यवनप्राश में भी चरबी को मिलावट की जाती है और लोगों को खिलाया जाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) :
आप यहीं खत्म कीजिए।

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मैं पूरी फाइल लेकर आया हूँ। हमारे साथी कहते हैं ये हैं प्रमुदत्त ब्रह्मचारी, इनकी चिट्ठी है मेरे पास। ये कहते हैं कि ऐसा काम करने वालों को फांसी दो। कमलापति जी कहते हैं कि फांसी दो। 5 P.M. जो काशी के, वाराणसी के शंकराचार्य है उनकी यह चिट्ठी है। उन्होंने लिखा है कि फांसी दो। इसी तरह मे जो मुस्लिम लोग ठेकेदार बनते हैं, यह कहते हैं मुसलमानों के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम एसोसिएशन लिखती है कि फांसी दो जिन्होंने हम को सूअर को चर्बी खिलाई। इस तरह की मेरे पास पांच सौ चिट्ठी हैं। मैं आपको दे सकता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) :
आप तशरीफ रखिये। कल्याण सुन्दरम जी आप बोलिये। रामेश्वर सिंह जी की कोई बात इसके आगे रिकार्ड में नहीं जायेगी। आप बैठ जाइये। हाउस में आपको इस वक्त बात करने की जरूरत नहीं है। जो चाहे आप कह लें लेकिन रिकार्ड पर आपका एक लफज भी नहीं जायेगा।

श्री रामेश्वर सिंह :*

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) :
आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइये। आपका कोई रिकार्ड नहीं हो रहा है।

श्री रामेश्वर सिंह :*

SHRI M. KALYANASUNDARAM
(Tamil Nadu): It appears as if we are giving a clean chit, but when I look at this controversy I do not know whether we are going to inspire confidence among the people that our political parties are competent enough to bring about the necessary socio-economic changes to satisfy them. Whether the import of tallow was allowed due to the wrong policy of the Janata Government or the negligence of the Congress-I Government subsequently, the fact remains that large quantities of animal tallow of all varieties have been landed in this country by unscrupulous fellows. How to tackle this problem is an important one, no doubt. You should have a scientific approach to this problem. The Government is in a haste. I do not know why this Ministry got so panicky that now they totally banned the import of all varieties of animal tallow. When you solve one problem, it should not give rise to another problem. I do not know what problems this is going to create for the people; we have to wait and see. Now, for what purpose is this tallow used? The Minister of Civil Supplies has categorically assured that there is no adulteration at the point of production. We are living in a society where adulteration, corruption and other kinds of misuse of power

*Not recorded.

[Shri M. Kalyanasundaram]

are quite common. More essential articles are adulterated. Show me a single item of essential articles which is not adulterated. Are we taking up this issue? Is it not our responsibility as political parties who go with liberal promises to the people at the time of election, to put down adulteration? Have we succeeded in it? In fact, adulteration itself has become a separate industry to produce articles suitable for adulteration—foodstuffs, drugs, etc. Even cement is not spared. Therefore, should we not take a wider approach to this problem of adulteration? Nobody has said that the mixture of animal tallow—whether it is beef tallow or pig tallow or any other animal tallow—with vanaspati is injurious to health. Nobody has said that. More serious adulterations are taking place which are more injurious to public health. People are getting all sorts of intestinal disorders and liver diseases after taking hotel food. Beef is sold as mutton because beef is cheaper than mutton. I have seen religious Hindus taking beef because it is cheaper. They are very good people. I won't consider them as less faithful to their religion. Such changes are taking place in our society. Why do you make such a fuss now on this issue?

SHRI RAMANAND YADAV: Those Hindus who take beef must be belonging either to CPI or CPM.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: I am a Communist. But I do not take mutton at all. Even eggs I do not take. I am a pure vegetarian.

SHRI RAMANAND YADAV : Why do you make a sweeping remark that Hindus take beef?

SHRI M. KALYANASUNDARAM : Please listen to my point. I am not suggesting that adulteration of fat with Vanaspati is good or bad. When more serious adulterations endangering the lives of people are taking place, when you come across cases of corruption and black-marketing, you do not show the same anger. That being so, why do you make this an issue just now? All of you have

to answer this question. Why do you shift the blame on the Janata Party?

SHRI SATYA PAL MALIK: They are bringing Sankaracharya on the T.V.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : Religion should not be involved in politics. When my CPM friend was speaking, there was so much of shouting and even Kari Marx was brought to the House. Marx said that religion is opium of man. What did he mean by that? Religion is used to make human beings dull like opium to divert their attention from the miseries which they are suffering from.

AN HON. MEMBER: That is what friend said.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : I have no friend or foe when I speak. I speak on policies. Therefore, do not interrupt me. Have some patience. I cannot speak in the way you want me to speak. (*Interruptions*). You have also election ambitions. Can you say that you have none? Do not attack me on mat ground.

I was explaining what Marx meant when he said that religion is opium of man. And he has proved to be correct. Our own experience is also that. Religion is used for diverting the attention of people from the wrong policies followed by the Government. If it used against the wrong policies of the Government, I will give my hand to Mr. Rameshwar Singh and join him. I cannot do it because it is ;<sed for a different purpose.

In what way is the import policy or the industrial policy of this Government different from that of the Janata Government? I can understand if there is a battle on policies. But there is only battle to mislead the people. Who can mislead the people better? That seems to be the race. And for that purpose you do not hesitate to use any weapon. That is- why my Party does not support your approach to this problem of tallow import. We have our own approach. Now you have totally banned import of animal tallow—all kinds of tallow. Let us see how soap is going to be manufactured. Will not the prices of soap go up? Do not shift the burden of your wrong policy to the people. When

there is so much of corruption, adulteration and black-marketing, no political party is bothered. Can any political party say that they are against these evils? You see, you pick up one issue and fight when it suits you. That is how it is done. But it is the system that is responsible for these evils. I ask my friends: Are you prepared to accept my suggestion? Now that you have seen how the import licence is misused, how the import licence can be misused, will you accept the suggestion of mine that the export-import trade must be taken over by the Government and no individual should be permitted to import anything? Will anybody support this in this House? I ask my friends who are concerned so much about this adulteration of vanaspati will tallow. Yes, come on. The second thing is this: The biggest importer of tallow is M/s Hindustan Lever. They are the biggest producers of vanaspati and soaps, all kinds of soaps. I am asking my friends: Will you support this demand? The Government is not prepared to do it. Will you urge upon the Government that this firm, M/s Hindustan Lever Ltd., and other such companies should be taken over by the Government so that the people can get these things at cheaper prices? Will they support this? I do not say that the Government is pursuing a right policy. It is a very wrong policy, from the point of view of the people and our national development. Their import policy is ruining many industries. Let US take the import policy and fight. Whether they are liberalising the import policy that was introduced recently or not, this is not the question that I should discuss now and this is not the time when I should talk of all these things. That is why I am not referring to them. But my point is that we must stand on the principle that the import policy or any other policy must serve the interests of the people and that should be the approach in this case also.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

Earlier, Sir, I sought a clarification from the Minister, Mr. Bhagwat Jha Azad, about the import consignments. Two consignments landed in Madras harbour. One was cleared, that is, before the ban under came. The final order comes only

in the end. But one batch landed there and I do not know why it landed in Madras only to be transported to Ghaziabad near Delhi, to this Company. Kindly verify this and also see what has happened to the remaining consignments. Kindly see whether they are also in the bonded ware-hous or are being stealthily removed.

Now, about the importers and exporters: The ruling party should be very careful. They use their intimacy with some leading figures and exploit it for their own ends. One such personality is Mr. Vinod Jain of the Shudh Vanaspati firm. He has got so many concerns under him. One is Jain Exports, and he is also an exporter and an importer and he is involved in scandals and he has preferred claims with the insurance companies and he is a very notorious figure and I am warning you now". When our friend on this side read out something from the "Onlooker", you only shouted at him. But you must know how it affects your prestige. Please see that. He claims intimacy with everybody. Can you allow such a fellow to exploit you? Should you not treat such people as untouchable? Should they not be treated as anti-social? They should not be allowed to come anywhere near the Prime Minister's house or the Prime Minister's office Or the Presidential palace. Such is the notoriety of the people of this type, of this character, a very shady character. I will give you whatever details you want. If you want details, I am prepared to give them about the anti-social activities of this firm which is involved in this controversy How. I do not know whether there is any rivalry between M/s. Hindustan Lever and this firm, Jain Shudh Vanaspati, to raise this controversy in this forum. Now, he has been allowed bank credit. He has been allowed unrestricted licences to import these things. He has been given Unlimited financial resources by banks. The most important three banks are the New Bank of India, the Punjab and Sind Bank and the Punjab National Bank. I have got the figures of the amount. He does not have even the initial deposit what is called the marginal deposit. He does not even have to produce any security for the large sums that he had drawn. He has drawn about Rs. 30 crores from the

[Shri M. Kalyanasundaram]

Punjab and Sind Bank, Rs. 14 crores from the New Bank of India and some amount from the Punjab National Bank. Unfortunately, the Finance Minister is not here. But the Finance Ministry has taken action against the officials who were responsible for giving Rs. 14 crores by the New Bank of India. But no action has been taken in the case of large-scale advances given by the Punjab and Sind Bank. What does it show? It shows this man's high connections in political circles. Why don't you get angry? Even if he is your friend, and if somebody donates to the party, can you think that they can purchase the party? Donations are permissible and that can be understood. But can anybody, any industrialist or this kind of smugglers, think of purchasing a political party and use their intimacy with political leaders for coercing the administration or coercing the officials to get the officers. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think you have made your point.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : I am sorry I am taking more of your time, The points are important. That is why...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have covered them now.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : I do not want to take any political advantage against this party. I want the country to be saved. I want the people to be protected from Smugglers, from black-marketeers, from such kind of exploiters. That is my concern. That's why. Thank you, - Sir.

SHRI A. G. KULKARNI: Mr. Deputy Chairman, the discussion, the Short Duration Discussion, which we have just now was replete with emotions, religion and so many other extraneous points that it did not bring out the correct position which ought to have been brought out. I agree with my friend, Mr. Kalyanasundaram, that we are entering into, and we have already entered into, the age of science, scientific thinking, scientific talent. Such religious sentiments should not be exploit-

ed. It is my personal position. And I take that position, because the country can only go forward to develop with the aid of science and technology. I do not know why this entire matter was blown out. Though I have got all affection for my young friend, Mr. Viswanath Pratap Singh, in the last session, while replying the unnecessarily allowed himself to be carried away by that bug, the Janata bug as it is called. Every Minister wants to quote Janata's faults. I was with your party to attack the Janata party. You have unnecessarily taken the initiative in discrediting the two parties. These two parties have not combined to take political advantage...

SHRI J. K. JAIN: You are Chairman of that party?

SHRI A. G. KULKARNI: My dear friend¹, you don't interrupt. You are the Secretary of a party. Why do you require that?

SHRI J. K. JAIN: What are you then'?

SHRI A. G. KULKARNI: I belong to the Congress Party which is the true Congress Party. (*Interruptions*) Mr. Jain youngsters should not interrupt when elders are speaking. (*Interruptions*)

SHRI J. K. JAIN: Then you should also behave like elders. (*Interruptions*) What I say is, behave like elders. (*Interruptions*).

SHRI A. G. KULKARNI: I think, Sir, that when Mr. Vishwanath Pratap Singh replied at that time, he stated that the Janata Government had liberalised it. Many times it is liberalised. Many times restrictions are imposed. It all depends on the ruling Government. Last year, when Mr. Pranab Mukherjee was the Commerce Minister, he further liberalised—not exactly in this point but inhere are many other liberalisations to the small scale industry, to aid technology, to aid industry. So, liberalisation or restriction depends on circumstances prevailing of the economy at that period of time. What I wanted to say was that when my good friend Mr. Ramanand

Yadav said liberalise import policy, somebody also replied from this side. Liberalise import policy means that Mr. Rama-nand Yadav cannot import. It is the actual user who has to import. You have to correct yourself. It is the actual user. In the case of Mr. Mohan Dharia's statement

SHRI RAMANAND YADAV: Under OGL anybody can import.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, when Mr. Mohan Dharia liberalised the import policy, it was nobody else except Mr. Pra-nab Mukherjee who congratulated Mr. Mohan Dharia for liberalising the import policy. He was sitting with us here on this side and you were on a back bench, and still you are on that side. So, the actual user licence has to be obtained. And I want to know categorically this thing. I am not satisfied with the answer given by Mr. Bhagwat Jha' Azad in the morning because as far as I am aware—I am also connected with industries—whenever an import licence has to be obtained, a capacity utilisation and requirement of the raw materials certificate has to be given by the DG—TD on the recommendation of the Department to which this industry belongs. In the case of textiles, suppose I want to import cotton, I have to go to the Textile Commissioner and get a certificate that I am entitled to such and such quantity of cotton, and then the Controller, as the policy may be either grants or rejects, and if it is canalised it comes through the STC or whatever it is. So, Mr. Minister, my basic question is how this Sudha Vanaspati man—my friend, Mr. Kalyanasundaram just now mentioned—was granted an import licence to import beef tallow? How these consignments came? Who allowed him? Who recommended his case? Which was the Ministry—the Industry Ministry or whatever it is? And in the reply given by Mr. Bhagwat Jha Azad in the morning, he mentioned 18 names of soap manufacturers who required tallow. That is what his contention was. Tallow is also required for incising in textile industry. Tallow is required to make candles. There are various uses, what they call the industrial uses of tallow. And don't unnecessarily fall prey to the political game being played now about

the sentiments whether of the Hindu people or the Muslim friends that the tallow should be totally banned. Don't do that foolish thing. Tallow is required in this country. And you may ban the tallow. But cow is being slaughtered. You have not banned cow slaughter. You have not banned slaughter of animals. Tallow is being produced, and it is being mischievously used by various adulterators. So, do not go on an emotional basis. Do not go on a religious basis. Behave like a scientific man. And what I want to ask is: How was this consignment imported? And who ordered? Whether it was the Finance Ministry or the Commerce Ministry, who ordered this? I do not allege, Mr. Commerce Minister, but it is rumoured that high personalities either in the Commerce or in the Finance Ministry instructed the Customs Department to let go these consignments of about 7,000 tonnes or 10,000 tonnes—which affidavit Mr. Advani read out in the morning—on a nominal fine. So, if somebody interprets that the hands of the ruling party are greased, he will not be off the mark. The point is not of importing tallow. I am not on this point. This is not my point. Tallow has to be imported, that is my point! But my question is who ordered this tallow to be imported and which was the Ministry concerned which asked the Customs Collectorate to let it go, because Jain Shudh Vanaspati are not soap manufacturers? You have not mentioned the name of Jain Shudh Vanaspati in the morning papers which you gave to us. The name of Jain Shudh Vanaspati is not there. DCM is there. The names of other companies are there. Jain Shudh Vanaspati is not a soap manufacturer. I want to know how an actual user licence was given to them. You are the Commerce Minister, and so should explain it. (*Interruptions*). So, corruption is involved in this. That is the basic point, which is really disturbing and I am only on that point. Secondly, in your September speech you said that it was the Janata Party which liberalised the policy. Let them liberalise or not liberalise, I am not concerned with it, because my view is

[Shri A. G. Kulkarni]

a very different view. But at that time adulteration was not possible at all. Any industrialist or a trader is not a fool. At that time the international tallow prices were between Rs. 13 to Rs. 14, while the groundnut oil prices were between Rs. 7 to Rs. 8 and vanaspati prices were between Rs. 8.50 and Rs. 9.50. Which fool would bring the imported tallow under the open general licence, as my friend Mr. Rama-nand Yadav said? He unnecessarily entered into a different field. Who would import it and mix it with a cheaper variety? Now, you know, the blame is on your Government, Mr. Minister, because at present vanaspati is sold at skyrocketing prices and international prices of tallow are cheaper. That is why it is being used. And I charge that your Government is to be blamed because since you assumed the power the power, you leave aside 1980, but in 1981-82 policy or 1982-83 policy, when the vanaspati and oil prices started rising, you should have been very careful in monitoring the use of tallow, either mutton, or pig or cow tallow, to the industrial uses only. This is my second point. You will have to justify your aspersions on the Janata Government or Mr. Mohan Dharia's policy, whatever it is. (*Time Bell rings*).

Sir, I want to make only two points. I have already asked you why the Jain Shudh Vanaspati, when they were not the actual users, were allowed to import beef tallow. That point you will have to reply. Then I want to say that in this tallow controversy, which is going on, there are religious sentiments. One must respect them. Mr. Rameshwar Singh was my guest some time back. He came to my place along with his wife. I know that she does not even drink water brought by somebody else. I know this because he came to my place at my home town. There are religious sentiments which one has to respect. But in all this affair bungling has been done by the import policy of your Commerce Ministry by not being careful enough to ban the import or channelise the import of this tallow when vanaspati prices started rising. (*Time Bell rings*). I am coming to

the end, Sir, and want to mention my last point. Mr. Jha says that so many samples were tested, etc. Two samples found and something in Ranchi etc. He might be correct because he is the Government. But it is very difficult to find out these things in villages and moffusil areas other in U.P., Bihar, Maharashtra, Gujarat, etc., because it is so cleverly mixed with vanas-pati. Nobody knows; and you can blame the States I don't mind; but it is very difficult for the State Governments, with their paltry machinery of monitoring, to do it. For this purpose, I would request that there must be some such other machinery. Now, you agreed about the size and you said that you will reduce the size of the tins and print on it. But printing also will serve only the educated persons, educated housewives. Adulteration has to be very strongly checked, and monitored and for this purpose, I feel why the people are so much disturbed is firstly because of religious sentiments, and secondly, the Jains which are notorious for corruption, have pocketed the Government. That is their allegation.

SHRJ GHUI-AM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): I thank you for allowing me to speak on this subject. Lot of heat has been generated on this issue. Although I belong to the Opposition, I fail to understand as to why this side or that side should make a political issue of a matter which is purely of a technical nature. The matter is very clear. When it is said from that side that in the Janata period, tallow was placed under O.G.L., it was under an import policy prevailing at that particular point of time. The import and export policy is framed by the Government every year. So, it follows that if the Janata Government had placed it under O.G.L., when the other Government came to power, why didn't they change it? But that is not the position. Every Government is a responsible Government. Why it was put under O.G.L. was in order to keep the wheels of the industry moving and therefore, open general licence had been resorted to, and one has to understand it in this context. If in 1978 Janata Government placed it under O.G.L. and now the Congress Government has also placed it under O.G.L., it is to meet the needs of the people and requirements, of the people.

But what is missing in this whole drama, (O my mind, is only one think Under this import policy, the basic thing is that the powers are vested with the Government of India. Section 2 says: "The Imports and Exports Control Act 1947 empowers the Central Government to prohibit, restrict or otherwise control imports and exports and in exercise of powers conferred by this Act, Import Control Order 1955 has been issued. Schedule 1 to the said Order contains list of articles of which import is controlled. Import of such items is prohibited except in accordance with licence and customs clearance permit issued under the said Order if they are covered under O.G.L. subject to such conditions as may be stipulated."

So, this is a power vested with the Commerce Ministry, and how it exercises this power.

With regard to O.G.L., as my friend Mr. Kulkarni said, Open General Licence does not mean that Mr. Shyam Lai Yadav or Mr. Matto cSh import it; it is only the actual user who is to import that particular commodity; even if it is under O.G.L., it may be licenced or under O.G.L., it has to be done by the "Actual user." With regard to actual user, again it is very clear under clause 5 which says: "Actual user means a person who applies for and secures a licence for import of any item on allotment of imported item required for his own use and not for business or trade in it. Thus in the case of an industrial undertaking, the item concerned shall be utilised for the manufacturing processes by operations conducted in its authorised premises." Now, even when the goods are being imported, the position which has been stated here is:

"All actual users at the time of clearance of goods shall furnish to the Customs authorities a declaration giving particulars of the industrial licence or registration as an actual user with the concerned authorities, namely, the number and date of the industrial licence/registration and the end product(s) manufactured and affirming that (i) the industrial licence has not been can-

celled or withdrawn are otherwise made inoperative and (i) the item imported under the OGL are strictly in accordance with the terms and conditions of their industrial licence/registration with the sponsoring authority as an industrial unit and their approved phased manufacturing programme."

Now, my P^{mt} is th^{*5}. Thk tallow has been imported. I do not agree with Mr. Allhabadi. I agree with my friends from the Opposition benches, that the religious sentiments of both the communities are involved in this, the Muslims as well as the Hindus. Muslims would not countenance the use of pig tallow, just as the Hindus would not countenance the import and use of beef tallow. But this has happened. I do not blame the Commerce Ministry at all. But what I say is that the monitoring agencies had not ensured the strict observance of the rules. For instance, if an OGL has been given to a soap manufacturing concern, how is it that a vamaspati manufacturing concern has used this? This is the point which should be answered.

My first point is, that it is very essential for the Government of India to ensure that the provisions of the Import Trade Order are strictly observed. My second point is a very important point. It is true that some people have made a political issue of this. This is very regrettable. Similarly, I feel that the Commerce Minister is also being carried away emotionally by this sentiment, say with authority—I am in the industry—that if you do not allow the import of tallow or a substitute for this tallow, then the price of a cake of soap in the next six months will soar to Rs. 10. As you know, soap is a commodity which I used in the Himalayas, in the desert by the poor, by the rich for washing purposes as well as for other purposes. Would like the Minister of Commerce to give a guarantee to this House that in spite of his being emotionally drawn by banning the import, he shall ensure that the country will not suffer and that there will be no shortage of soap and other things, in which this tallow is used. I would like to have the Minister's assurance for

[Shri Ghulam Rasool Matto]

the Commerce Minister. With these words, I conclude,

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, the debate has had its moments of storm and also moments of calm. I am glad, most of the hon. Members have taken a very even keel and have taken a balanced view of the problem. I am also thankful to those who have suggested correctives, particularly, to myself. But I believe, some of our senior Members have been driven off their feet by the gusto of their own arguments. Therefore, to conclude the debate, I will begin with the undebatable. That is, action. It is undebatable that Government has acted swiftly, quickly, firmly...

SHRI M. KALYANASUNDARAM: And hastily.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: . . . and it is being charged as having over-acted. But so far as action is concerned, it is undebatable. It is also undebatable that we have compromised with none. Perspective may be different but once we took a line of decision, we have not compromised with anyone, be it the highest and the 146 firms in which I have no liking for any reason because we feel that technically the licences that have been used *prima facie* were not in our preliminary examination, not in order according to the rules and the prevailing regulations. We have also pressed the CBI into action and 8 cases the CBI is looking into. Departmental proceedings have been started. Also, the stocks that have been there, provisions are being made, arrangements are being made for their appropriate disposal. So, there is nothing, not even a lurking suspicion in the mind.

A question has been raised that the Government has over-acted and reacted in haste. I do not think so. Religious sentiments are a matter which we cannot just waste away and it is true that the consideration of sentiments of the people Government did have in mind. But I regret to say that while this sensitivity the Government have shown and acted, some senior Members have made serious allegations against the party, and I think the

charges are like the party is being purchased, that money has been taken to suppress the case. Sir, this I say is ;< misuse of the floor of the House and I deny the charges. The action of the Government did not conform to any such allegation. If has conformed to anything, it is to the contrary, that the Government has not made any compromise and I assure that the Government will not compromise with whatever position or power of money one may hold.

So far as the action is concerned, I may draw the attention of Mr. Matlur in particular who may swear by the Vishva Hindu Parishad and other Members also here, they have congratulated the Government on the action and have said—I do not quote it as authority, but for some Members it may have some meaning and that is why I am quoting -that we are pleased to note from the letter No, so and so from the Joint Controller that in deference with the sentiments of the people the imports of all animal tallow, including the beef tallow, has been totally banned. This action by the Government has provided a great relief to the cow worshipping Hindu society. Well, the mind of the Vishva Hindu Parishad is at rest, but Mr. Mathur's mind is still not at rest, it is still agitated.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

That is because there is corruption involved. (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: It is a compromise.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: So far as the furture debate on the import is concerned, with the total ban the debate is closed. With every new day this debate is becoming debate of the past, as to who did what and when and if I were to say only this, some friends on the opposition may say, no, yet the blames have to be apportioned. Well, if that is so, I will not deny them their pleasure. I will do my best to present the facts. I will not shy away also from it. But what the present facts will say and what way the verdict will go, the risk is entirely theirs

Sir, What I said is not making an issue of it, politicising it or making a

big issue out of mentioning that it was brought on OGL during Janata Party's rule. I had to respond because in the other House—the Lok Sabha—an hon. Member of the House pointedly asked me when this item had come on OGL. How could I not reply to that? I was not politicising the issue. I had to furnish the date, I have to furnish the information that any Member ask. it is my bounden duty to furnish it. And why should the sensitivity of that party—because I mentioned something in answer to a Member which I could not refuse and which I was duty bound to give—be so much hurt that because of that answer, after that rallies were held, hunger strikes were organised, posters, were put on all media, at every level it was carried out *just to politicise the issue—just because of a simple answer in the House, this issue was blown up?* Who did it?

When it is blown up that way, we have to make our position clear. Sir, the issue is two-fold. One is of import and the other is if adulteration. Wish the calm atmosphere, the rationale that is prevailing in this House today—for which I am thankful to the hon. Members—would have prevailed the village, block and district level also. What is being preached day in and day out On all platforms, through all publicity materials is that there is a strong nexus between the imports and adulteration. This has been the line till now. I am thankful to the 'hon. Member who starred the debate and also some of the Members who have now said that import is not the issue. On adulteration point, my colleague has very clearly stated what the position is. But because there is this case being made out that there is a strong nexus, the import policy and its discussion become inevitable; it cannot be avoided. Because if you make an allegation against the Govt, of its intent, then the intent of the Government is codified in its policy and to analyse the intent of any Government. Its policy will have to be analysed, it will have to be contrasted, it will have to be compared. And it was only that, and it was not my intent to make any hit like that. But, Sir, there is a limit to hypocrisy. If a certain policy is made by me, well I have no right tomorrow to take a deffen-

rent stance and I must come out and admit that this has been the policy and whatever suggestions are there should come. That is the perspective. And if we look to the policy, Sir, if making policy is the main villain of the lot, then there has been a watershed at the policy level as soon as Janata Party assumed power. There was, as many Members have said, not the issue of import of tallow. There was a highly restrictive policy on import of tallow during the Congress rule earlier. It was not on OGL list. It was a canalised item. Under certain flexibilities, some could import in a very limited way for actual use. This was a highly restrictive policy. From this policy of restriction. Sir, from year to year there has been an opening of the gates towards imports of animal 'tallow. And these books stand testimony perhaps and as I look at the debate that is being carried on, I want to put this testimony before the House, and through the hon. Members to the people whom they represent, that this is a testimony which, just by raising, dust, if it is thought, that can be hidden. it cannot be hidden.

It cannot be hidden. Here it is on record. There are several notifications and regulations that have been made. I call upon those leaders who have gone on hunger strike, have held rallies and have made all these statements to come and put their hand on this book and say it does not have their sanction, it does not have their approval. And what are the sanctions that have been given? It is an eye-opener. I am a novice. I still feel a novice in this Ministry but, thanks to this debate, the whole labyrinth of policy making I could go into and every year and every policy book is a milestone on the path of liberalisation of import, of beef tallow and other tallows.

श्री रामेश्वर सिंह : क्या आप . . .
(व्यवधान) . . .

SHRI J. K. JAIN: No. He should not be allowed. He has spoken enough

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आदरणीय रामेश्वर सिंह जी जांच में नहीं बिठा रहा हूँ, मैं केवल आईना दिखा रहा हूँ । . .

[श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह]

Sir, here is the Import Trade Control Order in which it was brought under OGL when it was possible to bring beef tallow, etc., under OGL. It is dated 3rd April, 1978. The provisions have been made that if an item is not banned, restricted or canalised 01 it is not in appendices (3, 5, 6, 7, 8, and 9) that item will become OGL for actual user industries.

SHRI A. G. KULKARNI: Was it commercially possible?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I will come to each and every point—prices of oils, edible oils, etc.... (Interruptions). Please bear with me, Kulkarniji. I will try, to the best of my ability and sincerely, to answer each and every point ... (Interruptions)

श्री रामेश्वर सिंह : भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, बीफ टैलो कैसे मान लेंगे ... (व्यवधान) हमारे पास भी जानकारी है, हम भी देखकर बैठे हैं, जांच करा लीजिये । (व्यवधान)

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, this is one matter which came up in 1978. Now, Mr. Kulkarni and Mr. Matto were raising the point now, apart from actual users, other houses could use OGL. That is one specific question which has been haunting us. To other aspects and details about Mr. Jain, etc.. I will come later. Now I am on the general points. There has been a provision for export houses...

SHRI A. G. KULKARNI: Under Rep. licence.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: In their right as export and trading houses.

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमान, एक मिनट ...

SHRI J. K. JAIN: This is highly objectionable. He has no business to disturb like this.

श्री रामेश्वर सिंह : वहाँ मटन टैलो को क्या कीमत है और आपने किस प्राइज पर आयात किया ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am coming to that. Let me come to the point and tell you. On this an export house could buy a Rep. licence and it could also, on its own licence, buy items on OGL which were on OGL but because they abolished the list, there was no list. Anything on OGL could come there for export houses and that is how the opening was made wide through this provision.

And the Jain Shudh Vanaspati case is of diamond licence. A licence of diamond not that of beef tallow was endorsed. Under flexibility of OGL it was sought to be used. And REP transferability also was created during 1978. Flexibility of OGL and transferability of rape was created at that time.

SHRI A. G. KULKARNI: Now also it is there.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It took us some time to catch all the mischief that was going on. That is all. How could we think in a government.....?

SHRI A. G. KULKARNI: You are liberalising the imports. I know your policy is like that.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am not against liberalization as such, but I cannot be liberal or negligent when it concerns the sentiments or feelings of the people. One has to restrict when it hurts the people.

SHRI A. G. KULKARNI: That is why it has exploded. In the Janata period it never exploded.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: It took us time to notice that.

SHRI A. G. KULKARNI: It was commercially impossible to do it.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It could be claimed by my friends that this was an act of omission. When we generally liberalized, liberalization was a good thing. We forgot to put beef tallow or pig tallow into the

restrictive list-and it was just an oversight-granting them the best. Here is a Finance Ministry notification, which Mr. Jain asked for, which gives duty exemption. (Interruptions) Many a time he challenged that the Commerce Minister is misguiding and that every time the Commerce Minister has changed. Here is the Finance Minister who in 1979....

श्री जे० के० जैन : रामेश्वर जी, आपके आका बैठे हुए थे जिन्होंने ड्यूटी घटाई। कुछ शर्म करो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : मैं भी पढ़ूँ। (व्यवधान)

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: No, Sir. I am not yielding the floor. The hon. Member had all the time to read it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Now you have no chance..

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: This is of 27th April, 1979. Notification of Customs. To save time, I will not read it fully. In exercise of powers... being satisfied that it is necessary and in public interest so to do, hereby making the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 117-Customs.... dated 9th June 1978, viz. In the said Notification for the First Schedule, the following shall be substituted. That was for the Customs duty exemption. And what was substituted? This is an act of commission, not of omission. "Tats of bovine cattle".

श्री जे० के० जैन : बोली कितना रुपया खाया था उस समय ? किस किस ने दलाली की थी ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, it has to be kept on record.

SHRI A. G. KULKARNI: That was a single case. Now there are hundreds of cases.

श्री रामेश्वर सिंह : हम को भी पढ़ने दीजिये (व्यवधान)

SHRI J. K. JAIN: Don't talk. (Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. Do not disturb the Minister when he is replying.

श्री रामेश्वर सिंह : सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठाइये और जांच कराइये। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जज के पास भेज रहे हैं सब मुकदमों को। (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not touch the side issues. (Interruptions). Please take your seat.

श्री रामेश्वर सिंह : सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठाइये और सारे स्कैडल की जांच कराइये।

श्री भागवत झा आजाद : जनता से बड़ा जज कौन है ?

SHRI VISHWANATH PRAIAP SINGH: Sir, now having laid this foundation of the policy, they sanctified it and justified it. What did follow? And when what followed is considered, there has been a lot of tallow slinging during these three months. And if that is analysed, my friends from the Opposition will find their fingers deeply in tallow, not in ghee because each 6 P. M. page of their policy is smeared with tallow. Here I will present as to what followed thereafter. Many a time a case has been made as to how the arrivals have been made. And Mr. Kulkarni said that as the oil price was less, it could not come, that it was impossible to come because the market forces were like that. May I ask: Is the Government of India to run by its policy or by the market? Will every day the market quotations be seen and then the Government of India policy decided? The Government. Opens all the gates and says the market will take care of it.

SHRI A. G. KULKARNI: The charge is of adulteration because of your policy. There is nothing else.

SHRI J. K. JAIN: Whom does Mr. Kulkarni represent?

SHRI A. G. KULKARNI: adulteration took place. You cannot forget this. *(Interruptions)*. Do not try to defend. At that price it was not possible to bring tallow and mix it in oil. Now it is possible because you cannot control the price. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is quite capable. Please do not worry. *(Interruptions)* Please go on.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I will treat them with the best of intentions,

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: In framing your import policy would you or would you not take into account the international market and the domestic market situation?, I want to ask.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Yes, I will.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Do you not take into account the market situation? You take into account the price of soda when you liberalise the import of soda. Are you not taking into account the market situation?

SHRI A. G. KULKARNI: He is not addressing kindergarten boys. We know what we are talking. We are not kindergarten boys.

श्री जे० के० जैन : उपसभापति जी, भिस शर्मनाक तरीके से कुलकर्णी जी ने आज टैलो इम्पोर्ट करने के लिये कहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वे सोप मैनुफैक्चरर्स के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं ।
.. (व्यवधान)

श्री रामानन्द यादव : आप उन लोगों को बोलने के लिये अलाऊ क्यों करते हैं ?

श्री उपसभापति : जैसे आप खड़े हो गये, वैसे ही वे भी खड़े हो जाते हैं । आप क्यों खड़े हो गये बीच में ?

Yes, please go on. Do not stop. Please do not pick up those persons. Only the Minister will go on record; unless he sits down, nobody will go on record. Even interruptions will not go on record, either from this side or from that side.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am ready to re-state that the Janata Government was very conscious of the price. It was very conscious of the market, and it took the market to be more powerful than its policy and abdicated its policy to the market forces.

SHRI RAMESHWAR SINGH*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Do not take Mr. Rameshwar Singh. The Minister will go on record: nobody else.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: About taking the prices into account, the price of oil they evaluated, the price of tallow they evaluated, but the price of the feelings of the people they did not evaluate. That was left to the market. The analysis has shown...

SHRI A. G. KULKARNI:*

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: About the actual arrivals, a point is made many times that it has arrived during our time. Sir, between conception and delivery there is always some time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a long gap.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: And after they have laid these policy parameters, we have been able to analyse 307 licences. On the 5th June, 1981 we canalised all animal tallow.

*Not recorded.

So I have analysed only after 5th June, 1981. Previously you had made it sacrosanct. So what is arrived after 5-6-81 is during our period. But where from is the river flowing? Where is the mountain from which it has comes? And that we have been able to arrive at, that is, 307 licences have been issued before 5-6-81, that is, from April 1978 when the foundation was laid by the policy till it was restricted on the 5th June, 1981, it was either a registered export contract or a licence issued during that time that was operated now. And for this I have positive proof. Licence No. PW 2904470, dated 23-2-1979 used for import of beef tallow to M/s Bharat Diamond Industries, Bombay. Item imported: beef tallow. Quantity imported-. 1551.688 metric tonnes. Value in rupees; 68,08,967. It came on 1-3-83. It has come in our time. It is a licence of 23.2.79. (*Interruptions*) It is not childish. You're behaving like a woman who has given birth to a child but does not want to own the child and puts it at somebody else's door. That is how you are behaving. You own up your children.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:*

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH; You own up your children. They are coming like litter. Licence No. PW 2875547, dated 3-9-79, to M/s George Maijo Madras. Value imported: Rs. 11,17,000-I am not reading' the hundreds. Same licence; again the same party; value Rs: 12,24,000. Then licence No. PW 285171 of M/s. Kajaria Exports. Calcutta. Value imported; Rs: 53,52,000. Then licence No. PW 2918217-M/s LB. Exports. Rs. 40.11,000. Then same licence Rs. 41,13,000. Then licence No. PW 2895197. M/s. Alam Tanneries Calcutta. Rs. 17 lakhs Then licence No. PW 2859226, dated 16-3-79; value imported: Rs; 27,70,000. I can go on like that. There are 307 licences...

SHRI A. G. KULKARNI: * SHRI

L K. JAIN: * *Not recorded

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH; These licences constitute about 73 per cent.

SHRI RAMESHWAR SINGH.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH; I am reading Mr. Mohan Dharia's statement. (*Interruptions*) The hon. Member wanted to know about Mr. Mohan Dharia's statement.

SHRI RAMESHWAR SINGH⁵

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH.- The hon. Member wanted to know about it. He says he has not made such a statement. This is a xerox copy of *Indian Express*, dated 29th October, Bombay. Therein it was written that about 25,000 tonnes of beef tallow was imported by about 5,000 actual users in 1977-78. And he frankly said, "What is wrong in importing the same if it is needed for genuine industrial purposes?" (*Interruption*) They are charged with giving legality to such imports. They are charged with putting their sanction on the statue book; they are charged with! giving exemption from duty. And now when they go on the streets and condemn it, they are only condemning themselves and nobody else. So much talk has been made about graft, corruption, higher-ups, this, that. May I ask what this graft is about? (*Interruptions*) Will you admit it? It is very easy to say. things. I am asking Mr. Mafhur; nobody else said it...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Yes, I stand by it. There was graft The ladies of the particular household have been going round and saying to (*Interruptions*)

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am not saying this to Mr. Kulkarni and all my reasonable friends who have taken a very reasonable stand. I am taking this stand only because... (*Interruption*) All this preference of hunger strike and all that cannot give sanction to what you have done. ' This is the green book they have issued. Ours is red. This is the green flag for all. the

*Not recorded.

[Shri Vishwanath Pratap Singh]

beef tallow and pig tallow. Can you deny your signature and approval of it? So, don't shout now. *(Interruptions)* At least Mr. Mohan Dharja has been a man but others are not even a half man. Mr. Morarji Desai says that he knew that beef tallow was coming. A senior member in the Cabinet, why did he not speak up? All right, you were not manly enough to speak up then, but when the whole nation gave you all the power and made you the Prime Minister, even then, you had no courage to speak up or do anything. He instituted all kinds of inquiries, set up all intelligence all round the world to find out what wrongs Mrs. Indira Gandhi had done, what the Congress had done, dug up even the house of Mrs. Indira Gandhi here in Delhi, instituted a Shah Commission, invited all people to give evidence. When he had this lethal secret in his heart, he could have brought out that lethal secret so that all this effort would not have been accessory. Why did he keep quiet? In fact, there was nothing like that. So they had to keep mum. They have no alibi now. And then, about adulteration. Is it your case that whenever the Congress comes, then adulteration starts, and when it is over there is...

SHRI A. G. KULKARNI: How can it be? Nobody will say that.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It was said import is not the issue. May I say adulteration is also not the issue?

SHRI A. G. KULKARNI: What about the beef tallow which was imported through Madras?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I will tell you about that.

Apart from the present situation, there have been periods in our political history when the Congress was in power in the Centre and a large number of States were ruled by other Parties. If large-scale adulteration at the factory level was going on, how was it that not one case was de-

tected. Even NTR and Hegde have not found adulteration and it was Darbara Singh who found out adulteration. It was our Government and our Customs officers who detected it and it was we who banned it. And now people who have acted are at fault. How can a politically adulterated Government catch cases of adulteration? Imbecility is not the hallmark of any Government.

SHRI A. G. KULKARNI: How can you adulterate something worth Rs. 13/-a kg. with another thing which is worth Rs. 7/-kg?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It is just like Lok Dal tallow being mixed with BJP which is another (allow which are of different prices).

SHRI A. G. KULKARNI: You please light with them.

SHRI IAGDISH PRASAD MOTHUR: Your Congress (1) tallow is being mixed with Russian tallow . . . *(Interruptions)*.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Shri Kulkarni asked about the Madras consignment. Mr. Vice-Chairman, I have already said that I will place everything before the House and I have nothing to conceal so that people will know about it. The question was about Madras consignment. I have got the information regarding Bombay consignment. I will get the information about the Madras consignment and place it here. The Bombay consignment is also for 10,700 tonnes. I am giving that information. I will tell you what I have got. M/s. Jain Shudh Vanspati has requested for reshipment of 10,495 tonnes of beef tallow. The importer has been asked to produce no objection certificate from the Reserve Bank of India. This case was sent to CCI for comments by the Department of Economic Affairs. They have been informed that in this case permission for re export cannot be given as the import is clearly unauthorised and this consignment is liable to confiscation.

This is the latest position.

SHRI A. G. KULKARNI: It was not confiscated. It is on file only,

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: This is a different case.

SHRI A. G. KULKARNI: What has happened to that shipment? Is it still lying in Bombay?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: This is not allowed in the country. This will not be allowed.

SHRI A. G. KULKARNI: I agree with Mr. Singh. He has no information. I agree. It was allowed because of the telephone from Delhi. (Interruptions). That is the allegation.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Mr. Kulkarni, this is not that one.

SHRI A. G. KULKARNI: I know it. (Interruptions)

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Then why are you mixing it up? I am coming to that one. Regarding this he claimed again, "My contract was before 5th June 1981". That is one is lying. And, about what you are saying, for which he has gone to the court, he is saying, "My contract for the import of beef tallow was before 5th June 1981.", That is, the policy was started during the Janata period in April 1978 and came to a terminus on the 5th June 1981. He is claiming that under that very policy it has been done. (Interruptions).

SHRI A. G. KULKARNI: He has given an affidavit that it has been released to him. The affidavit was read out in the morning. What do you want to say on that? (Interruptions).

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I will answer that. If you want, I will answer that and leave out the other points. If there is any doubt in the honourable Member's mind, I will answer that. You see, on that matter, the Customs proceedings are quasi-judicial proceedings and the officer under the quasi-judicial proceedings is not under the direction of the Government. The collection "has gone in appeal in that case for a greater fine and for a greater punishment and

has not compromised with that situation (Interruptions).

SHRI J. K. JAIN: Very good.

श्रीमता उषा मल्होत्रा : हंसराज गुप्ता वाली बात के बारे में बताइये ।

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, so far as my information goes, it is like this. (Interruptions). Mr. Mathur has said that Mr. Hans Raj Gupta had resigned from M/s Jain Shudh Van-aspati. He at least testifies to the association of Mr. Gupta with Jain Shudh Vanaspati. Till what date?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: He had resigned long back. (Interruptions) He was there from 1970 to 1975. (Interruptions).

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, my information is that during the Janata period, in 1978 or in 1979, Mr. Hans Raj Gupta became one of the Directors of Ajanta Tubes which is also connected with it. (Interruptions).

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: He resigned from that also. (Interruptions).

श्री जे० के० जैन : तुम्हारा मुंह काला हो चुका है। यन् सारी चीज इम्पोर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप क्या बोल रहे हैं ... (व्यवधान) तीन साल पहले रिजाइन कर दिया था। ही नोज इट। (व्यवधान)

श्री जे० के० जैन : अजन्ता ट्यूब कम्पनी के अन्दर ये डाइरेक्टर हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ये।

श्री जे० के० जैन : अगर अब हो तो क्या तुम इस्तीफा दोगे ? (व्यवधान) अजन्ता ट्यूब कम्पनी के डायरेक्टर अभी

[श्री जे० के० जैन]

भी है। क्या तुम इस्तीफा दोगे अगर वह हो ? (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं हैं।

श्री जे० के० जैन : इसका मतलब साफ है। अगर इनके अन्दर हिम्मत है तो यह मेरा चैलेंज स्वीकार करें। अगर वह अजन्ता ट्यूब के डायरेक्टर हो तो क्या आप इस्तीफा दोगे ? (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इस बात का यह सबूत है कि इनके पास और कोई बात कहने का नहीं था इस लिये यह अजन्ता ट्यूब वाली बात ले आये। आपको कोई ढंग की बात कहनी चाहिये थी। अजन्ता ट्यूब का बीफ टैली के साथ क्या संबंध है। वह इसके डायरेक्टर है नहीं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अजन्ता ट्यूब के डायरेक्टर की लिस्ट और जैन वनस्पति धों के डायरेक्टर्स की लिस्ट उठा कर देख लीजिये... (व्यवधान)

श्री जे० के० जैन : यह सारा अगर एस एस का किया हुआ काम है। यह साबित हो चुका है। (व्यवधान)

MR. Mathur should resign (Interruption)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने भी पैसा खाया होगा, ऐसा मालूम होता है। (व्यवधान)

SHRI VISHWANATH PRATAP SJNGH: Sir, Mr. Ladli Mohan Nigam raised certain points and it is a very difficult point. He mentioned about the specification and there is much substance in what he says, that is, that there is overlapping of specifications between the various types of tallow. The authorities also have this and they have gone through this-this is Bailey's Book on Fats and Oils and this is the world authority on this

and they also say that there is a lot of overlapping. There is difference in the values of the various types of tallow, in the saponification value. There is a varying range of values.

But there is one value. The unsaponifiable matter of beef tallow is above .5, while that of mutton tallow upto .5. This has been borne out by Bailey's book, page 343. (Interruptions) It is Bailey's Industrial and Fats Product... (Interruptions) The unsaponifiable percentage is .74 for North American beef, and for goat; Indian, it is .18. So there is...

श्री लाडली मोहन निगम : मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि मटन टैलों के लिये और दूसरे टैलों के लिये आप जो यह परपोजन दे रहे हैं, यह यहां के काऊ टैलों में और वहां काऊ टैलों में होता है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या आपने कोई स्पेसिफिक टैस्ट कराया है जिससे यह साबित हो कि इस में बीफ टैलों मिला हुआ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आई० एस० आई० के स्टैंडर्ड्स हैं।

श्री लाडली मोहन निगम : मैं यही कह रहा था कि आपके स्टैंडर्ड से यह संभव नहीं है, आप यह साबित नहीं कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आई० एस० आई० से ज्यादा नालेज तो हमारा नहीं है। आई० एस० आई० को हमें मानना पड़ेगा।

श्री रामेश्वर सिंह : मैंने शुरू में ही कहा था कि चाहे बीफ टैलों हो या मटन टैलों हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। टैलों के नाम से बिकता है।

श्री सैय्यद सिकते रज्जी (उत्तर प्रदेश) : टैलों की स्पेलिंग क्या है? बता सकते हो।

श्री अजयल रहमान शेख : ये शूड हिन्दुस्तानी हैं, फिर्गी नहीं हैं।

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: So we have to be very clear. Shri Kalyanasundaram made one point and other hon. Members also made it that so far as the availability and adulteration are concerned, availability does not necessarily mean adulteration. Tallow has been available for thousands and thousands of years in this country. But banning of import of tallow - well, if any calf or pig is born it will not require an import licence of the Comemrce Ministry to be born. So there are social forces. As my hon. colleague said, factory workers are there. They are conscious. And many times the employer has to throw out a worker—retrenchment, action is taken, and so on. There are so many other circumstances and we have to be alert and act against these unsocial elements. There I agree. Here we should come together rather than fight amongst ourselves, to fight these unscrupulous people. And I will beg of some of the Members on the opposite benches not to see in every Vanaspati tin a ballot box. (*Interruptions*)

SHRI M. KALYANASUNDARAM: What about banks which have allowed them so much of credit - Rs. 14 crores, Rs. 13 crores by the Punjab and Sind Bank, the New Bank of India and the Punjab National Bank? You may not be concerned with it directly. But should you not ask the Finance Minister to enquire from these banks and ask them not

to be so liberal in the grant of letters of credit for importers of this kind?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I have made a note of this, and I will communicate it. I plead that while we may pursue any objective, Sir, it gives a lot of agony to innocent people and the scare can put emotional stress. Sometimes the population has also to undergo psychological stress. And there is the communal side also. So, all these possibilities we have to take into consideration, and in a rational way we have to approach it and present it. And certainly we should not compromise with anybody who is doing wrong. So, I would request that let us join hands to fight the unscrupulous elements rather than we fight amongst ourselves as to who are doing or who are likely to do such things.

So, Sir, these are the comments that I have to offer.

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही
कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की
जाती है ।

The House then adjourned at thirty-one minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 17th November, 1983.